https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने
विधानसभा में साबित किया बहुमत

वर्ष-12, अंक-07, 01-15 अप्रैल, 2017 (पाक्षिक) ₹20

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में भाजपा सरकारों ने ली शपथ

दशकों तक देश गलत दिशा में चलाः नरेंद्र मोदी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देश को स्वस्थ और मजबूत बनाएगी

भारत अब अनाज का निर्यात करने वाला देश

महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट करते
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मिलते
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

आदित्यनाथ योगी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

06

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 325 सीटों पर अपना परचम लहराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। राष्ट्रीय विचारों से ओत-प्रोत एवं जुझारु भाजपा नेता श्री आदित्यनाथ योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में दूर तक लहराते केसरिया झंडे, जोश से...

वैचारिकी

चिति 15

श्रद्धांजलि

राष्ट्र निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर 17

साक्षात्कार

प्रकाश जावडेकर, *केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री* 20

श्याम जाजू, *भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश प्रभारी* 24

लेख

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देश को स्वस्थ और मजबूत बनाएगी 22

अन्य

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एस.एम.कृष्णा भाजपा में शामिल 15

दशकों तक देश गलत दिशा में चलाः नरेंद्र मोदी 26

भारत अब अनाज का निर्यात करने वाला देशः केन्द्रीय कृषि मंत्री 30

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टप्स के लिए निधि स्थापित करने को मंजूरी दी 31

अटल मिशन (अमृत) के तहत उत्तर प्रदेश में 11,421 करोड़... 32

प्रधानमंत्री निवास पर भाजपा सांसदों के साथ बैठकें 33

संगठनात्मक गतिविधियां

09 त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

भाजपा नेता श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 मार्च को उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में...

11 मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने विधानसभा में साबित किया बहुमत

गोवा के बाद मणिपुर में भी भाजपा सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री...

सरकार की उपलब्धियां

12 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

नई स्वास्थ्य नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता दिए जाने के साथ-साथ स्वास्थ्य खर्च को समयबद्ध...

14 मंत्रिमंडल ने चार जीएसटी विधेयकों को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 20 मार्च को जीएसटी से...

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

आइए, विश्व जल दिवस पर जल की एक-एक बूंद बचाने की प्रतिज्ञा करें। जब जनशक्ति अपना मन बना लेती है तो हम जलशक्ति बचाने में सफल हो सकते हैं।

@nitin_gadkari

सीसीईए ने पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय पथ विकास के लिए 6000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का अनुमोदन किया है, जो 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में आगे बढ़ने के लिए एक प्रमुख कदम है।

@JPNadda

'स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण' सुरक्षा, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के युग का संदेश देने वाला है।

facebook

दीनदयाल उपाध्याय- एक वैकल्पिक चिंतक के रूप में, जब प्रत्येक व्यक्ति साम्यवाद, पूंजीवाद में व्यस्त था तब 'मानवतावाद' की विचारधारा सामने लेकर आए।

-अमित शाह

आतंकवाद विश्व के लिए बड़ा खतरा है, जिसे विश्व के राष्ट्र अधिक सहयोग के साथ निपट सकते हैं। हमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई आतंकवाद की व्यापक परिभाषा को स्वीकार करना ही होगा। जो राष्ट्र इस परिभाषा का उल्लंघन करेंगे, उन्हें दण्डित और बहिष्कार करना होगा।

-राजनाथ सिंह

दिल्ली सरकार कई नगर विकास परियोजनाओं पर कार्रवाई करने में विफल रही। इसी कारण वह प्रगति नहीं कर पा रही है।

-एम. वेंकैया नायडू

व्यंग्य चित्र

साभार : नवी दुनिया

'कमल संदेश' के सुधी पाठकों को

श्री रामनवमी

की हार्दिक शुभकामनाएं!

पाथेय

भारतीय जनता पार्टी को देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका अदा करने के लिए कहा गया है। जैसे एक किसान किसी फसल को उगाने से पहले मिट्टी की किस्म और पर्यावरण का अध्ययन करता है, उसी प्रकार हमारी पार्टी को अनिवार्य रूप से उस समाज के स्वभाव को पूरी तरह समझना होगा, जिसमें हम कार्य कर रहे हैं।

-कुशाभाऊ ठाकरे

भूल सुधार

कमल संदेश (16-31 जनवरी, 2017) में **'श्रद्धांजलि'** स्तंभ के अंतर्गत **'नहीं रहे सुंदरलाल पटवा'** शीर्षक समाचार में उनकी धर्मपत्नी के विषय में गलत सूचना छप गयी थी, जिसका हमें खेद है। स्व.पटवा जी की पत्नी स्वस्थ हैं, ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनायें।

नए भारत की ओर

गोवा और मणिपुर के पश्चात् भाजपा सरकारों ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में भी अपना दायित्व संभाल लिया है। आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश तथा त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इन प्रदेशों में भ्रष्टाचार, कुशासन एवं अकर्मण्यता का युग समाप्त हो चुका है तथा लोग अब भाजपा सरकारों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। भाजपा सरकारों ने अपने सकारात्मक पहलों से भविष्य के लिए शुभ संकेत दिये हैं और लोग परिवर्तन का अनुभव कर भी रहे हैं। अखिलेश सरकार के फरार मंत्री गायत्री प्रजापति जिसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पकड़ा नहीं जा सका था, सरकार बदलते ही तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी सरकारी मशीनरी में नया आत्मविश्वास जगा है और सरकारी कार्यकलापों में गंभीरता दिखाई पड़ रही है। केवल सरकार बदलने से सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों में भय या पक्षपात के बिना कार्य करने का संदेश गया है और वे बदली हुई राजनैतिक व्यवस्था में अपना कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर हैं। हर क्षेत्र में कार्य-संस्कृति में व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा है।

विधानसभा के इन चुनावों ने हर राजनैतिक दल को महत्वपूर्ण संदेश दिये हैं। जिस प्रकार का प्रचंड जनादेश जनता ने दिया है उससे अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि विकासपरक कार्य करने की क्षमता रखने वाली तथा दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व में घिसी-पीटी लीक से हटकर निर्णय ले सकने वाली सरकारें अब जनता चाहती है। समाज को जाति-मजहब तथा क्षेत्रीयता में बांटकर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने की कांग्रेस-सपा-बसपा की आदत उन पर भारी पड़ी है। इनके खोखले नारों में लिपटी हुई विभानजकारी राजनीति को जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भाजपा पर हमला करने के लिए झूठ एवं फरेब की राजनीति तथा केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जबरदस्ती नकारने के कारण इनकी इतनी करारी हार हुई है। हर क्षेत्र में भयानक नाकामियों के बावजूद जिस प्रकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा अखिलेश सरकार ने पीटना चाहा उससे क्षुब्ध होकर जनता ने सपा को उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से धूल चटा दी। इसी प्रकार से उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार के भ्रष्टाचार एवं मणिपुर में कांग्रेस की नाकामियां इनकी हार के कारण बने। कांग्रेस-सपा-बसपा को जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब समाज में तोड़-फोड़ करके तथा भय एवं संदेह का वातावरण बनाकर वे चुनाव नहीं जीत सकते। साथ ही नकारात्मक राजनीति तथा केवल भाजपा विरोध से वे जनता द्वारा निरंतर भारतीय राजनीति के हाशिये पर धकेले जाते रहेंगे, लेकिन इसमें भी किसी को संदेह नहीं की कांग्रेस तथा इसके सहयोगी दल इस जनादेश से कोई सबक ले पाने की भी स्थिति में अब नहीं बचे।

इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय राजनीति में विकास एवं सुशासन की राजनीति शुरू करने का श्रेय भाजपा को जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की करिश्माई एवं दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व में पार्टी को भारी जनविश्वास मिला है तथा नये भारत का लक्ष्य राष्ट्रीय जीवन को एक नई प्रेरणा दे रहा है। प्रचंड जनादेश के सामने विपक्ष इतना हताश हो गया है कि अब इवीएम मशीनों को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है।

इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय राजनीति में विकास एवं सुशासन की राजनीति शुरू करने का श्रेय भाजपा को जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की करिश्माई एवं दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व में पार्टी को भारी जनविश्वास मिला है तथा नये भारत का लक्ष्य राष्ट्रीय जीवन को एक नई प्रेरणा दे रहा है। प्रचंड जनादेश के सामने विपक्ष इतना हताश हो गया है कि अब इवीएम मशीनों को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है। इतना भारी जनादेश विरोधियों के लिए अकल्पनीय है तथा अब वे पूरी तरह बेबस दिखाई दे रहे हैं। यह कार्यकुशलता, ईमानदारी, प्रामाणिकता, प्रतिबद्धता एवं लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा की ही शक्ति है कि भाजपा के विरोधियों को जनता हर बार पहले से भी अधिक करारा जवाब दे रही है। परिवर्तन का जादू जो पूरे देश में गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, जनजाति, वंचित, युवा एवं महिला के लिए चल रहे अनगिनत कार्यक्रमों के द्वारा चल रहा है उससे हरेक व्यक्ति के मन में एक विकसित एवं वैभवपूर्ण भारत के लिये आकांक्षा प्रबल हुई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ठीक ही कहा है कि परफॉरमेंस एवं विकास की राजनीति देश के एजेण्डे पर होना चाहिए। इस प्रचंड जनादेश को अमित शाह ने पहले ही भांप लिया था तथा विरोधियों के इसे मोदी सरकार की उपलब्धियों पर रेफरेंडम मानने की चुनौती को खुलकर स्वीकार किया था। इन विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत से देश में विकास एवं परफॉरमेंस की राजनीति मजबूत हुई है और यह देश के भविष्य के लिए एक शुभ संदेश है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

आदित्यनाथ योगी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा उपमुख्यमंत्री व 44 बने मंत्री

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 325 सीटों पर अपना परचम लहराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। राष्ट्रीय विचारों से ओत-प्रोत एवं जुझारु भाजपा नेता श्री आदित्यनाथ योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में दूर तक लहराते केसरिया झंडे, जोश से सराबोर भाजपा कार्यकर्ता का उत्साह देखते ही बनता था। कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान जोरदार नारे भी लगाए।

'सबका साथ–सबका विकास' का नारा देकर 14 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी 19 मार्च को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ हो गई। मंच पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दोपहर दो बजकर बीस मिनट पर श्री आदित्यनाथ योगी के 32 वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते ही उत्तर प्रदेश में एक नए युग की शुरुआत हो गई।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने योगी के साथ उनके सहयोगी के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इनके अलावा योगी के मंत्रिमंडल में 44 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, वरिष्ठ पार्टी नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, सपा संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और श्री नारायण दत्त तिवारी, कई केंद्रीय मंत्री व 13 प्रांतों के मुख्यमंत्री इस अवसर के साक्षी रहे।

कांशीराम स्मृति उपवन में आयोजित भव्य समारोह में कुल 22 कैबिनेट, नौ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 13 राज्यमंत्रियों ने शपथ ली। इस मंत्रिमंडल में वरिष्ठता और अनुभव को तरजीह दी गई। गठबंधन के सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को भी भागीदारी मिली।

नई टीम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। विकास का कीर्तिमान बनेगा। हमारा एकमात्र मिशन और उद्देश्य विकास है। जब उत्तर प्रदेश विकास करेगा तो भारत विकास करेगा। हम उत्तर प्रदेश के युवाओं की मदद करना चाहते हैं और उनके लिए नए अवसर पैदा करना चाहते हैं।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

'15 दिन में संपत्ति घोषित करें मंत्री'

कुर्सी संभालने के कुछ देर बाद मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने 'सबका साथ–सबका विकास' नीति पर सरकार चलाने की घोषणा

की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां करेगी। कार्य में पारदर्शिता रहेगी। मंत्रियों को पंद्रह दिन के अंदर अपनी चल–अचल संपत्ति का ब्योरा मुख्यमंत्री के सचिव व भाजपा की प्रदेश इकाई को उपलब्ध कराना होगा।

लोकभवन में नवनियुक्त मंत्रियों से भेंट के बाद पत्रकारों से मुखातिब मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 वर्षों से जारी भ्रष्टाचार, परिवारवाद और कानून व्यवस्था की बदहाली ने प्रदेश का भारी नुकसान किया है। इन प्रकरणों पर कार्रवाई होगी। सरकार बिना भेदभाव के समान रूप से कार्य करेगी। गरीब, दलित, पिछड़ों के लिए विशेष प्रयास होंगे। राज्य सरकार नागरिकों को अच्छा भोजन, आवास, पेयजल, शौचालय और कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए कार्य करेगी। परिवहन व्यवस्था दुरुस्त होगी। प्रयास होगा कि कृषि प्रदेश के विकास का आधार बने, क्योंकि प्रदेश का बड़ा हिस्सा खेती पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की व्यवस्था को भ्रष्टाचारविहीन व पारदर्शी बनाया जाएगा। रोजगार के अवसर सृजित होंगे। महिलाओं को समान अवसर दिया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ : एक परिचय

उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए श्री आदित्यनाथ योगी (श्री अजय सिंह बिष्ट) का जन्म 5 जून 1972 को उत्तरकाशी में हुआ था। वे 15 फरवरी 1994 को गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया है।

योगी आदित्यनाथ का नाम लोकसभा में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के सांसदों की सूची में भी शामिल है। गोखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसके बाद 1998 में वह सांसद चुने गए। योगी आदित्यनाथ जब 12वीं लोकसभा में सांसद बनकर पहुंचे तब उनकी उम्र मात्र 26 साल थी। इसके बाद आदित्यनाथ 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी लगातार सांसद चुने जाते रहे।

सितंबर 2014 में उनके गुरु महंत श्री अवैद्यनाथ के प्राण त्यागने के बाद वह गोरखपुर मंदिर महंत यानी पीठाधीश्वर बने। योगी आदित्यनाथ भाजपा के सांसद होने के साथ साथ हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। हिन्दू युवा वाहिनी युवाओं का एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है।

मुख्यमंत्री
आदित्यनाथ योगी

उपमुख्यमंत्री
केशव प्रसाद मौर्य
डॉ. दिनेश शर्मा

कैबिनेट मंत्री
सूर्य प्रताप शाही
सुरेश खन्ना
स्वामी प्रसाद मौर्य
सतीश महाना
राजेश अग्रवाल
रीता बहुगुणा जोशी
दारा सिंह चौहान
धर्मपाल सिंह
एसपी सिंह बघेल
सत्यदेव पचौरी
रमापति शास्त्री
जयप्रताप सिंह
ओमप्रकाश राजभर
बृजेश पाठक
चौधरी लक्ष्मी नारायण
चेतन चौहान
श्रीकांत शर्मा
राजेन्द्र सिंह उर्फ मोती सिंह
सिद्धार्थनाथ सिंह
मुकुट विहारी वर्मा
आशुतोष टंडन
नंदगोपाल गुप्ता नंदी

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
अनुपमा जायसवाल
सुरेश राणा
उपेन्द्र तिवारी
डॉ. महेन्द्र सिंह
स्वतंत्र देव सिंह
भूपेन्द्र चौधरी
डॉ. धर्म सिंह सैनी
अनिल राजभर
स्वाति सिंह

राज्य मंत्री
गुलाबो देवी
जयप्रकाश निषाद
अर्चना पाण्डेय
जय कुमार सिंह जैकी
रणवेन्द्र सिंह धुन्नी
अतुल गर्ग
नीलकंठ तिवारी
मोहसिन रजा
गिरीश यादव
सरदार बलदेव सिंह औलख
मन्नू कोरी
संदीप सिंह
सुरेश पासी

उ.प्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्या और श्री दिनेश शर्मा एवं समस्त मंत्रिमंडल को बधाई।

मुझे विश्वास है कि श्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास एवं प्रगति के नए मापदंड स्थापित करेगा और साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आएगा और आमजन में सुरक्षा की भावना जाग्रत होगी।

— अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

सरकार संकल्प पत्र–2017 में किए गए सभी वादे पूरे करेगी। किसी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। राज्य में विकास व सुशासन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

– आदित्यनाथ योगी, मुख्यमंत्री

निवेश बढ़ाने का प्रयास होगा। कैबिनेट में लिए गए फैसलों का ब्योरा देने के लिए मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा व मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को नामित किया गया है।

भाजपा गठबंधन के सभी 325 विधायकों को संसदीय आचरण के तौर–तरीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए मंत्री श्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है। प्रशिक्षण की तिथियां जल्द घोषित होगी। इसमें संसदीय कार्य के विशेषज्ञ व केंद्रीय नेता भी हिस्सा लेंगे। ■

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

भाजपा नेता श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 मार्च को उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल श्री कृष्णकांत पॉल ने रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे। साथ ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह, सुश्री उमा भारती एवं श्री जगत प्रकाश नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री सर्वश्री रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूड़ी एवं भगत सिंह कोश्यारी के साथ ही निवर्तमान मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता श्री हरीश रावत भी मौजूद रहे।

श्री रावत राज्य में भाजपा के पांचवें मुख्यमंत्री हैं। पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी पहली सरकार साल 2000 में बनाई थी, जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर यह राज्य बना था। नित्यानंद स्वामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे।

नौ मंत्री बनाए गए

श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनके नौ सदस्यीय मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलायी गई। श्री सतपाल महाराज, श्री हरक सिंह रावत, श्री मदन कौशिक, श्री अरविन्द पांडेय, श्री सुबोध उनियाल, श्री यशपाल आर्य और श्री प्रकाश पंत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। श्रीमती रेखा आर्य और श्री धन सिंह रावत ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली।

मंत्रिमंडल सदस्यों का परिचय इस प्रकार है– श्री प्रकाश पंत उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। वह पिथौरागढ़ से विधायक हैं। श्री हरक सिंह रावत कोटद्वार से विधायक बने। श्री यशपाल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे। श्री सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से विधायक हैं। नारायण दत्त तिवारी सरकार में पर्यटन सलाहकार थे। श्री धन सिंह रावत श्रीनगर से विधायक हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। वह पहली बार विधायक बने। श्री मदन कौशिक हरिद्वार से विधायक हैं। वह सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले विधायकों में शामिल हैं। राज्य बनने के बाद वह लगातार चुनाव जीते। श्रीमती

@AmitShah

उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एवं उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों को हार्दिक बधाई।

त्रिवेंद्र सिंह रावत : एक परिचय

श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इतिहास से एमए किया है तथा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है। श्री रावत 1983 से 2002 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और उस दौरान वह उत्तराखंड अंचल और बाद में राज्य के संगठन सचिव रहे। 56 वर्षीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोइवाला सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समय वह पार्टी की झारखंड इकाई के प्रभारी हैं। वह पहली बार 2002 में डोइवाला सीट से विधायक बने। तब से वहां से तीन बार चुने जा चुके हैं। वह 2007–12 के दौरान राज्य के कृषि मंत्री भी रहे।

प्रधानमंत्री ने दी रावत को बधाई

प्रधानमंत्री ने श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर अपनी बधाई दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा – 'श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और उनकी पूरी टीम को शपथ ग्रहण करने पर मेरी बधाई। मुझे विश्वास है कि वे कड़ा परिश्रम करते हुए जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। राज्य के जनता जनार्दन द्वारा उत्तराखंड की नई सरकार को दिए गए भारी समर्थन और प्यार को वे राज्य में रिकार्ड विकास करके दिखाएंगे।

रेखा आर्य सोमेश्वर से विधायक हैं। सतपाल महाराज सांसद भी रहे हैं। चौबट्टाखाल से विधायक हैं। श्री अरविंद पांडे गदरपुर सीट से विधायक हैं।

सर्वसम्मति से रावत चुने गए नेता

गत 17 मार्च को भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षकों केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री सरोज पांडे की उपस्थिति में हुई पार्टी विधानमंडल दल की बैठक में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। बैठक के बाद श्री तोमर ने संवाददाताओं को बताया कि श्री रावत के नाम का प्रस्ताव पिथौरागढ़ के विधायक श्री प्रकाश पंत और चौबट्टाखाल के विधायक सतपाल महाराज ने रखा जिसका समर्थन कोटद्वार से विधायक श्री हरक सिंह रावत, हरिद्वार के विधायक श्री मदन कौशिक, यमकेश्वर से विधायक सुश्री रितु खंडूरी तथा कई अन्य विधायकों ने किया।

युवाओं को तरजीह देंगे

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सरकार राज्य के नौजवानों के स्वर्णिम भविष्य के लिए ठोस कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं, उन्हें कड़ाई से शुरू किया जाएगा। भ्रष्ट अफसरों को भी चिन्हित किया जाएगा। ■

मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने विधानसभा में साबित किया बहुमत

गोवा के बाद मणिपुर में भी भाजपा सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बिरेन सिंह ने 20 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 33 विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया। साथ ही भाजपा के श्री यमनम खेमचंद सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। श्री बिरेन सिंह ने 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

भाजपा के लिए यह पहला मौका है जब मणिपुर में उसकी सरकार बनी। बता दें कि 11 मार्च को चुनावी नतीजे आने के अगले दिन भाजपा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। राज्य के विधानसभा चुनावों में भाजपा दूसरे क्रमांक पर थी लेकिन वह राज्य में पहली बार सरकार बनाने की स्थिति में आई। 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में भाजपा की 21 सीट हैं। भाजपा को एनपीपी और एनपीएफ के 4–4 और लोक जनशक्ति पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के 1–1 विधायकों का समर्थन मिला। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी भाजपा को समर्थन दिया है।

खेमचंद मणिपुर विधानसभा के नये अध्यक्ष चुने गये

भारतीय जनता पार्टी के श्री युमनाम खेमचंद को मणिपुर विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। श्री खेमचंद (54) जाने माने ताइक्वोंडो विशेषज्ञ हैं और वह पहली बार सींगजामेई विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गये हैं। राज्य के मुख्यमंत्री श्री एन बिरेन सिंह ने कहा कि श्री खेमचंद संतुलित व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। उनसे उम्मीद है कि वह निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखेंगे।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओकराम इबोबी सिंह और कांग्रेस नेता श्री गोविंद दास और श्री के मेघाचन्द्र ने श्री खेमचंद के नये अध्यक्ष चुने जाने का स्वागत करते हुये उनसे बिना भेदभाव के काम करने की अपील की। ■

श्री एन बीरेन सिंह और उनकी टीम को शपथ लेने पर बधाई । मुझे विश्वास है कि उनकी टीम मणिपुर के विकास के लिए अथक रूप से काम करेगी।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मैं विश्वास दिलाता हूं कि मोदीजी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मणिपुर की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार विकास और प्रगति के लिए निरंतर कार्य करेगी। मणिपुर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित एवं प्रगतिशील उत्तरपूर्व के स्वप्न को साकार करने का काम करेगा। मैं भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मणिपुर के नए मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह जी,उनके मंत्रिमंडल एवं सभी साथी दलों को बधाई देता हूं।

अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017
वंचित तबकों के लिए बेहतर सुविधाएं
15 साल बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पेश

नई स्वास्थ्य नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता दिए जाने के साथ-साथ स्वास्थ्य खर्च को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने तथा सार्वजनिक अस्पतालों में नि:शुल्क दवाएं मुहैया कराने एवं अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल करने पर जोर दिया गया है।

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने 15 मार्च को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को मंजूरी दी। इस नीति के जरिए देश में 'सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं' मुहैया कराने का प्रस्ताव है। दरअसल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने कई सालों से लंबित स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी। यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 बनाई है। पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में बनाई गई थी। इस प्रकार, यह नीति बदलते सामाजिक-आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी-विज्ञान परिदृश्य में मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 15 साल के अंतराल के बाद अस्तित्व में आई है।

भारत सरकार ने नीति निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक सहभागितापूर्ण और परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रारूप को 30 दिसंबर, 2014 को पब्लिक डोमेन पर डाला गया था। इसके बाद नीति को और अधिक कारगर बनाने के लिए राज्य सरकारों और अन्य पणधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इस नीति को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद, जो शीर्ष नीति निर्माण निकाय है, के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसकी एकमत से पुष्टि की गई।

नीति में इसके सभी आयामों-स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्त-पोषण करने, विभिन्न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिए रोगों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, चिकित्सा प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने, मानव संसाधन का विकास करने, चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहित करने, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित ज्ञान आधार बनाने, वित्तीय सुरक्षा कार्यनीतियां बनाने तथा स्वास्थ्य के विनियमन और उत्तरोत्तर आश्वासन के संबंध में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने में सरकार की भूमिका और प्राथमिकताओं की जानकारी दी गई है। इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों, विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है।

नीति का लक्ष्य सभी विकास नीतियों में एक निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल दिशानिर्देश के माध्यम से सभी वर्गों के लिए

स्वास्थ्य और कल्याण का उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करना तथा इसके परिणामस्वरूप किसी को भी वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना बेहतरीन गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। इसे उपलब्धता का विस्तार करके, स्वास्थ्य देखभाल प्रदानगी की गुणवत्ता में सुधार करके तथा लागत को कम करके प्राप्त किया जा सकता है। नीति के व्यापक सिद्धांत व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठा और नैतिकता, निष्पक्षता, सामर्थ्य, सार्वभौमिकता, रोगी केन्द्रित तथा परिचर्या गुणवत्ता, जवाबदेही और बहुलवाद पर आधारित हैं।

नीति में रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर बल देते हुए रुग्णता-देखभाल की बजाय आरोग्यता पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा की गई है। हालांकि नीति में जन स्वास्थ्य प्रणालियों की दिशा बदलने तथा उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई है, इसमें निजी क्षेत्र से कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की भी नए सिरे से अपेक्षा की गई है। नीति में निजी क्षेत्र के साथ सुदृढ़ भागीदारी करने की परिकल्पना की गई है।

एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, नीति में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया

है। नीति में उत्तरोत्तर वृद्धिशील आश्वासन आधारित दृष्टिकोण की वकालत की गई है। इसमें 'स्वास्थ्य और आरोग्यता केन्द्रों' के माध्यम से सुनिश्चित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का बड़ा पैकेज प्रदान करने की परिकल्पना की गई है तथा यह अत्यधिक चयनित से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज में महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें प्रमुख एनसीडी, मानसिक स्वास्थ्य, जराचिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, उपशामक परिचर्या तथा पुनर्वास देखभाल सेवाएं शामिल हैं। इसमें प्राथमिक परिचर्या के लिए संसाधनों के व्यापक अनुपात (दो-तिहाई या अधिक) आवंटन करने की हिमायत की गई है। इसका उद्देश्य प्रति 1000 की आबादी के लिए 2 बिस्तरों की उपलब्धता इस तरह से सुनिश्चित करना है ताकि आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर इसे उपलब्ध कराया जा सके। इस नीति में उपलब्धता तथा वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभी सार्वजनिक अस्पतालोंमें निःशुल्क दवाएं, निःशुल्क निदान तथा निःशुल्क आपात तथा अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

नीति में विशिष्ट मात्रात्मक लक्ष्यों को भी निर्धारित किया गया है,जिनका उद्देश्य 3 व्यापक घटकों अर्थात् (क) स्वास्थ्य स्थिति और कार्यक्रम प्रभाव, (ख) स्वास्थ्य प्रणाली निष्पादन, तथा (ग) स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण के द्वारा बीमारियों को कम करना है जो नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप हों। नीति में जिन कुछेक प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है वे निम्नलिखित हैं:-

जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन

1. जन्म के समय आजीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 2025 तक 70 करना।
2. 2022 तक प्रमुख वर्गों में रोगों की व्याप्तता तथा इसके रुझान को मापने के लिए विक्लांगता समायोजित आयु वर्ष (डीएएलवाई) सूचकांक की नियमित निगरानी करना।
3. 2025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर टीएफआर को घटाकर 2.1 तक लाना।

आयु और/या कारणों द्वारा मृत्यु दर

1. 2025 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 करना तथा एमएमआर के वर्तमान स्तर को 2020 तक घटाकर 100 करना।
2. नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना तथा मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को 2025 तक घटाकर "एक अंक' में लाना।

रोगों की व्याप्तता / घटनाओं में कमी लाना

1. 2020 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसे एचआईवी / एड्स के लिए 90:90:90 के लक्ष्य के रूप में भी परिभाषित किया गया है अर्थात् एचआईवी पीड़ित सभी 90% लोग अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में जानते हैं–एचआईवी संक्रमण से पीड़ित सभी 90% लोग स्थायी एंटीरोट्रोवाइरल चिकित्सा प्राप्त करते हैं तथा एंटीरोट्रोवाइरल चिकित्सा प्राप्त करने वाले सभी 90% लोगों में बॉयरल रोकथाम होगी।
2. 2018 तक कुष्ठ रोग, 2017 तक कालाजार तथा 2017 तक स्थानि बीमारी वाले क्षेत्रों में लिम्फेटिक फिलारिएसिस का उन्मूलन करना तथा इस स्थिति को बनाए रखना।
3. क्षयरोग के नए स्पुटम पाजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की इलाज दर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना तथा नए मामलों की व्याप्तता में कमी लाना ताकि 2025 तक इसके उन्मूलन की स्थिति प्राप्त की जा सके।
4. 2025 तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता को घटाकर 25/1000 करना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर एक-तिहाई करना।
5. हृदवाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को 2025 तक घटाकर 25%करना।

इस नीति में गैर-संचारी रोगों की उभरती चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह समन्वित दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जिसमें द्वितीयक स्तर पर रोकथाम सहित सर्वाधिक प्रचलित एनसीडी की जांच से रुग्णता को कम करने और रोकी जा सकने वाली मृत्यु दर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा।

नीति में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्पना की गई है जिसमें क्रॉस रेफरल, सह-स्थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियां शामिल हैं। इसमें प्रभावी रोकथाम तथा चिकित्सा करने की व्यापक क्षमता है, जो सुरक्षित और किफायती है। योग को अच्छे स्वास्थ्य के संवर्धन के भाग के रूप में स्कूलों और कार्यस्थलों में और अधिक व्यापक ढंग से लागू किया जाएगा।

विनियामक परिवेश में सुधार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए नीति में मानक तय करने के लिए प्रणालियां निर्धारित करने तथा स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। यह नीति रोगी आधारित है और इसमें रोगियों को उनकी सभी समस्याओं का निदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नीति में औषधियों और उपकरणों का सुलभता से विनिर्माण करने, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने तथा तथा चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने की भी अपेक्षा की गई है। यह नीति व्यक्ति आधारित है, जो चिकित्सा परिचर्या चाहता है।

नीति में मध्य स्तरीय सेवा प्रदायक कैडर, नर्स प्रेक्टिशनरों, जन स्वास्थ्य कैडर का विकास करने की हिमायत की गई है ताकि उपयुक्त स्वास्थ्य मानव संसाधन की उपलब्धता में सुधार हो सके।

नीति में स्वास्थ्य सुरक्षा का समाधान करने तथा औषधियों और उपकरणों के लिए मेक इन इंडिया को लागू करने की परिकल्पना की गई है। इसमें जन स्वास्थ्य लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा उपकरणों तथा उपस्करों के लिए अन्य नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है।

नीति में नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट प्रदानगी तथा उपलब्धियों सहित एक समयबद्ध कार्यान्वयन ढांचा लागू करने की परिकल्पना की गई है। ■

मंत्रिमंडल ने चार जीएसटी विधेयकों को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 20 मार्च को जीएसटी से संबंधित निम्नलिखित चार विधेयकों का 20 मार्च को मंजूरी प्रदान कर दीः

- *केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 (सीजीएसटी विधेयक)*
- *समन्वित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 (आईजीएसटी विधेयक)*
- *यूनियन टेरीटरी वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 (यूजीएसटी विधेयक)*
- *वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक, 2017 (मुआवजा विधेयक)*

उपरोक्त चारों विधेयकों को जीएसटी परिषद द्वारा पिछले छह महीनों में आयोजित परिषद की 12 बैठकों में पूर्णरूपेण, खण्ड दर खण्ड विचार के उपरान्त पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। सीजीएसटी विधेयक में केन्द्र सरकार द्वारा अन्तः राज्य वस्तु अथवा सेवाओं पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं। दूसरी ओर, आईजीएसटी विधेयक में वस्तु अथवा सेवाओं अथवा केन्द्र सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं की अन्तः राज्य सप्लाई पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं।

सीजीएसटी विधेयक में केन्द्र सरकार द्वारा अन्तः राज्य वस्तु अथवा सेवाओं पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं।

यूटीजीएसटी विधेयक में विधान के बगैर संघ क्षेत्रों में वस्तु एवं सेवाओं के संघ क्षेत्र इतर संग्रहण पर अधिभार के प्रावधान किए गए हैं। संघ क्षेत्र जीएसटी के सदृश राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) जो राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा राज्य इतर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की सप्लाई पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) लगाया जाएगा। संविधान के खण्ड 18 (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यक्रम के फलस्वरूप राज्यों को होने वाले नुकसान के लिए इस मुआवजा विधेयक में मुआवजे का प्रावधान रखा गया है।

पृष्ठभूमि

सरकार सबसे बड़े कर अर्थात् वस्तु एवं सेवा कर को देश में जल्द से जल्द लागू करने के लिए वचनबद्ध है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने एक जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर की प्रारंभिक तिथि का निर्णय किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि वाणिज्य एवं उद्योग जगत को वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधानों के बारे में राष्ट्रव्यापी तौर पर स्थित को स्पष्ट करने के प्रयास किए जाएंगे।

जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के लिए सीमा एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 मार्च को सीमा एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में सेसों के उन्मूलन और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर अधिभार के संबंध में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन को अनुमोदित किया। अनुमोदित प्रस्ताव निम्न है।

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन
2. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन
4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम अपील, 1985
5. अधिनियमों के अधीन प्रावधानों के संशोधन या निरसन, जिसके तहत उपकर लाया जाता है

उपरोक्त प्रस्तावों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लाभ होंगे

—सीमा शुल्क अधिनियम,1962 में धारा 108ए और 108बी के सम्मिलन में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा माल के आयात/निर्यात से संबंधित सूचनाओं को प्रस्तुत करने का प्रावधान है ताकि आयात और निर्यात में अप्रत्यक्ष/अति-मूल्यांकन के मामलों का विश्लेषण और पता लगाने, निर्यात का दुरुपयोग दोष योजना और कस्टम अधिनियम के प्रावधानों और अन्य कानूनों के उल्लंघन सहित प्रचार योजनाएं शामिल हैं, जिसके अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों को इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

—अन्य अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के संशोधन या निरसन, जो अब जीएसटी की भूमिका के लिहाज से संगिक नहीं होंगे, परिणामस्वरूप संविधि पुस्तक से अप्रासंगिक भागों को शुद्ध किया जाएगा और करों की बहुलता को कम किया जाएगा। ■

चिति

भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एकात्म मानवदर्शन के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशताब्दी वर्ष (2016-17) में पाठकों के वैचारिक प्रबोधन के लिए हम उनके लेखों का पुनर्प्रकाशन कर रहे हैं। निम्न लेख 1947 के 'राष्ट्रधर्म' मासिक के अंक-6 में प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत है लेख का अंतिम भाग-

दीनदयाल उपाध्याय

केवल धर्म के भाव अथवा अभाव के कारण ही एक स्थान पर एक को बुरा मानते हैं तो दूसरे स्थान पर उसी को अच्छा कहते हैं। इसी के लिए देशद्रोही विभीषण परम वैष्णव हुआ और सुई के बराबर भी भूमि न देने को तैयार दुर्योधन विष्णुद्रोही गिना गया। एक ओर राजभक्ति को हमने माना है तो धर्म के लिए ही ऋषियों ने वेन को राज्यच्युत किया था। धर्म के लिए ही श्रवणकुमार अपने माता-पिता को कंधे पर लिए-लिए घूमा, धर्म के लिए ही प्रह्लाद ने हिरण्यकश्यप का विरोध किया। राम ने एक पत्नी-व्रत का पालन करके धर्म की रक्षा की तो कृष्ण ने अनेकों विवाह करके उसी धर्म को निभाया। अपने इतिहास में अनेक ऐसे श्रद्धास्पद उदाहरण मिलेंगे जिनमें इस प्रकार का विरोधाभास होगा, उनकी निराकृति केवल धर्म के भाव से ही संभव है।

हम अपने जीवन में धर्म को महत्त्व देकर ही प्रत्येक कार्य करते हैं। हमारा उठना-बैठना, सोना, खाना-पीना सबके पीछे धर्म का भाव रहता है। इसलिए स्मृति ग्रंथों में उनके संबंध में नियम दिए गए हैं। स्मृति-ग्रंथों को सभी धर्म-ग्रंथ मानते हैं। हमारा साहित्य लोक-कल्याण की धार्मिक भावना से ही प्रेरणा लेता है। कवि अपनी रचना 'स्वान्तः सुखाय' करते हुए भी अंतःकरण में आत्मा के साक्षात्कार की अनुभूति में सुख लेता हुआ धार्मिक प्रवृत्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। क्या कोई कवि भारत में हुआ है जिसके काव्य के एक-एक पद में राष्ट्रात्मा की पुकार हो और वह धार्मिक भावना से परिपूर्ण न हो। हमारे बाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसी, सूर, ज्ञानदेव, समर्थ, चैतन्य और नानक कवि थे, साथ ही ऋषि और संत भी थे। हमारे धर्म को अपने आचरण में लाने वाले आदर्श महापुरुष थे। इसीलिए उनके शब्द राष्ट्र के शब्द हो गए हैं। उनकी वाणी युग-युग में राष्ट्र जीवन का संचार करती आई है। हमारे राजनीतिज्ञ, आचार्यों ने भी राजनीति पर धर्म का पुट चढ़ाया है। शुक्राचार्य और चाणक्य धर्मविहीन राजनीति के पोषक नहीं थे। धर्महीन राजनीति का कोई अर्थ ही नहीं है। हमारे सम्राटों ने अश्वमेघ यज्ञ धर्म समझकर किए या राजनीति समझकर? राणा प्रताप का अकबर से युध्द राजनीति के क्षेत्र में आता है या धर्म के क्षेत्र में। शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह राजनीतिक नेता हैं या धार्मिक। दयानंद और विवेकानंद के कार्य का भारत की राजनीति और राष्ट्र पर क्या कोई प्रभाव नहीं है? गांधीजी के भारतव्यापी प्रभाव के पीछे उनका महात्मापन, उनका धार्मिकपन है या राजनीति? स्वदेशी आंदोलन में फाँसी के तख्ते पर गीता की प्रति लेकर चढ़नेवाले क्रांतिकारी वीरों में धार्मिक प्रेरणा थी या राजनीतिक? हम देखते हैं कि दोनों को अलग नहीं कर सकते। हमारी राजनीति हमारी धार्मिक वृत्ति का ही परिणाम है, अपनी धार्मिकता की रक्षा करने की एक साधन-मात्र है। यह धार्मिक प्रवृत्ति हमारे राज्य में इतनी व्यापक है कि उससे कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहता। वर्णाश्रम धर्म समाज की एक प्रणाली है, किंतु हमने इसको धर्म की वेशभूषा से सुसज्जित किया है। विवाह एक जीवन और समाज की आवश्यकता है, हमने इसको धर्मकृत्य माना है। संतानोत्पत्ति हम धर्म समझकर करते हैं और संतान भी माता-पिता की सेवा धर्म समझकर ही करती है। मरने के बाद श्राद्ध क्रिया भी धर्म मानकर की जाती है। यद्यपि इन सब कार्यों की तह में समाज रचना, जाति की सनातन परंपरा तथा

> कवि अपनी रचना 'स्वान्तः सुखाय' करते हुए भी अंतःकरण में आत्मा के साक्षात्कार की अनुभूति में सुख लेता हुआ धार्मिक प्रवृत्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है।

राष्ट्रत्व है। हम नित्य बड़े-बूढ़ों की वंदना करते हैं यह हमारा धर्म है। हम नित्य स्नान करते हैं यह गांव का कोई भी व्यक्ति बताएगा कि उसका धर्म है। इसलिए कर्मकांडी लोग बीमारी की अवस्था तक में स्नान करते हैं। बिना स्नान नहीं रह सकते। बिना स्नान के भोजन न करना धर्म ही है। कुएं पर जूते ले जाना अधर्म है। भोजन की स्वच्छतापूर्वक बनाना धर्म है। अपने-अपने घर में तुलसी हम धर्म समझकर ही रखते हैं, वह मलेरिया नाशक है, यह समझकर नहीं। स्वच्छता और स्वास्थ्य के सभी नियम धर्म बन गए हैं। हमारा कृषक बीज बोता है, उसके पीछे धर्म भावना छिपी है। धर्म भावना के कारण ही, चाहे आज वह विकृत क्यों न हो गई हो। बहुत स्थानों पर ब्राह्मण हल को हाथ नहीं लगाता है। विद्यार्थी गुरु की सेवा करता है, गुरु विद्यार्थी को पुत्रवत् मानता है, इन दोनों के पीछे धर्म की भावना है। जितने ही उदाहरण हम लें सबमें हमें यह दिखाई देगा कि हमारी धार्मिक प्रवृत्ति रही है। जीवन के प्रत्येक कृत्य को हमने धार्मिक रंग में रँगा है और धर्म से प्रेरणा लेकर ही हमने अपने जीवन की रचना की है।

भारत का राष्ट्र जीवन युग-युग में भिन्न-भिन्न स्वरूप में व्यक्त हुआ है, किंतु उसके मूल में उसकी धर्म भावना रही है और इसीलिए अनेक विद्वानों ने कहा भी है कि भारत धर्मप्राण देश है। आज अपनी इस आत्मा की प्रेरणा को अचेतन से चेतन के क्षेत्र में लाने पर ही राष्ट्र जीवन में जो विकृति दिखाई देती है, जो विक्षुब्ध, संघर्षमय, अनिश्चितता की अवस्था है, वह दूर की जा सकती है। ■ *-समाप्त*

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एस.एम.कृष्णा भाजपा में शामिल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के सान्निध्य में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री एस एम कृष्णा ने 22 मार्च को कई अन्य समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भाजपा का सदस्यता प्रपत्र और पुष्प गुच्छ देकर श्री एस.एम.कृष्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनंत कुमार, श्री सदानंद गौड़ा, कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री आर अशोक एवं कई अन्य गणमान्य नेता भी उपस्थित थे।

श्री कृष्णा 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। 1968 में पहली बार मांड्या से सांसद चुने जाने वाले श्री कृष्णा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में भी केन्द्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद मनमोहन सिंह कैबिनेट में उन्होंने विदेश मंत्री का ज़िम्मा संभाला और फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे।

इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि मैं हृदय की गहराइयों से बड़े हर्ष एवं आनंद के साथ श्री कृष्णा जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा कि श्री कृष्णा जी के पास लंबे सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, साथ ही विभिन्न दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास रूपी परिवर्तन की लहर चल रही है, देश हर मोर्चे पर सफलता की नई कहानियां लिख रहा है, ऐसे में श्री कृष्णा जी का भाजपा में शामिल होने का फैसला बहुत समयोचित है। उन्होंने कहा कि श्री एस.एम.कृष्णा जी के भाजपा में शामिल होने से कर्नाटक में भाजपा की ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही यह देश में साफ़-सुथरी राजनीति के प्रति भी एक संदेश है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए देश को विकास के पथ पर आगे ले जाना है।

> 'प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की 'पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस' एवं 'अंत्योदय' के सिद्धांतों पर चलते हुए देश के गांव, गरीब व किसान की भलाई के लिए लागू की गई नीतियों में गहरी आस्था है।'

इस अवसर पर श्री कृष्णा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की 'पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस' एवं 'अंत्योदय' के सिद्धांतों पर चलते हुए देश के गांव, गरीब व किसान की भलाई के लिए लागू की गई नीतियों में उनकी गहरी आस्था है। ■

राष्ट्र निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जीवन राष्ट्र और दीन-हीनों की सेवा के लिए समर्थित था। उनके सामने जहां एक तरफ करोड़ों दुःखी-पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न था, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र हित का सतत संवर्धन भी था। डॉ. अम्बेडकर का व्यक्तित्व सिर्फ दलितों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका योगदान समूचे भारत के लिए था। वे पूरे भारत के नेता थे। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के हित में काम किया।

अपनी माता-पिता की चौदहवीं संतान के रूप में जन्मे डॉ. भीमराव अम्बेडकर (14 अप्रैल 1891-06 दिसंबर 1956) जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात आर्थिक कारणों से वह सेना में भर्ती हो गए। उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर बड़ौदा में तैनाती मिली। अपने मित्र कैलुस्कर की प्रेरणा और महाराजा बड़ौदा की आर्थिक मदद से भीमराव उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। वहां के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर उन्होंने अपनी अध्ययनशीलता का परिचय दिया। 1917 में डॉ. अम्बेडकर भारत लौटे और देश सेवा के महायज्ञ में अपनी आहुति डालनी शुरू की। महाराजा कोल्हापुर के सहयोग से उन्होंने मराठी में 'मूक नायक' नामक पाक्षिक पत्र निकालना शुरू किया। वह 'बहिष्कृत भारत' नामक पाक्षिक तथा 'जनता' नामक साप्ताहिक के प्रकाशन तथा संपादन से भी जुड़े।

उन्होंने विचारोत्तेजक लेख लिखकर लोगों को जगाने का प्रयास किया। डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। उन्होंने देश के दलित वर्ग को मुखर होने की ताकत दी। 'संविधान प्रारूप समिति' के अध्यक्ष के रूप में वह भारतीय संविधान के निर्माता बने। मार्च 1952 मे उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा के लिए नियुक्त किया गया और वे मृत्यु तक इस सदन के सदस्य रहे। 6 दिसंबर 1956 को डॉ. अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हे मरणोपरांत 'भारत रत्न'के अलंकरण से सम्मानित किया।

(14 अप्रैल 1891-06 दिसंबर 1956)

'संविधान प्रारूप समिति' के अध्यक्ष के रूप में वह भारतीय संविधान के निर्माता बने। मार्च 1952 मे उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा के लिए नियुक्त किया गया और वे मृत्यु तक इस सदन के सदस्य रहे।

राष्ट्रहित सर्वोपरि

डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में राष्ट्रहित सर्वोपरि था। इसलिये वे मुस्लिम विघटनकारी शक्तियों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उनमें हिन्दुओं के साथ सह-अस्तित्व की बुनियादी भावना का अभाव है। इसके बिना देश की उन्नति असंभव है, इसी परिप्रेक्ष्य में सन् 1940 में उन्होंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग पर अपने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे पठनीय हैं। डा. साहब ने वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अंग्रेजों के इस दुष्प्रचार का खण्डन किया कि आर्य इस देश में बाहर से आए थे, तथा वर्तमान के शूद्र लोग आर्य नहीं हैं। उन्होंने यह बात आग्रहपूर्वक कही कि आर्य कोई वंश नहीं है तथा आर्य कहीं बाहर से नहीं आए। उन्होंने यह सुस्थापित किया कि शूद्र भी आर्य हैं। इस प्रकार आर्यों के बाहर से आने वाले सिद्धांत को उन्होंने मनगढ़ंत और निराधार बताया।

बाबा साहब का जीवन इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ही उसका निर्माण करता है, उसकी जाति, पारिवारिक निर्धनता, असुविधायें और समाज का विरोध उसकी प्रगति को रोक नहीं सकता। बाबा साहब का संपूर्ण जीवन युवकों के लिये प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने देश की युवा शक्ति से परिश्रमी तथा गुण संपन्न बनने का आहवान किया। बाबा साहब कहते हैं- 'सम्मान की आकांक्षा करना कोई पाप नहीं है, परंतु कार्य करते-करते सम्मान प्राप्त नहीं होता है, तो निराश होकर आप संघर्ष मत छोड़िये। यदि दुर्भाग्य से आप उस सम्मान से वंचित कर दिये जाये जिसके वास्तविक अधिकारी आप है फिर भी आप धैर्य न छोड़ें।'

डॉ. अम्बेडकर की सामाजिक और राजनैतिक सुधारों का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनकी सामाजिक और राजनीतिक सोच का सारे राजनीतिक हलकों में काफी सम्मान हासिल हुआ। उनकी इस पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज के भारत की सोच को प्रभावित किया। उनकी यह सोच आज की सामाजिक, आर्थिक नीतियों, शिक्षा, कानून और सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से प्रदर्शित होती है। संविधान निर्माण के महान राष्ट्रीय कार्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है। डॉ. अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना कि लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। मसौदा तैयार करते समय डॉ. अम्बेडकर ने अपनी विद्वता और कार्य निष्ठा के चलते अपने सहयोगियों और समकालीन प्रेक्षकों की काफी प्रशंसा अर्जित की।

डॉ. अम्बेडकर की सामाजिक और राजनैतिक सुधारों का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनकी सामाजिक और राजनीतिक सोच का सारे राजनीतिक हलकों में काफी सम्मान हासिल हुआ।

26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद डॉ. अम्बेडकर ने कहा, 'मैं महसूस करता हूं कि संविधान, साध्य (काम करने लायक) है, यह लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में, मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नही होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था।'

24 सितम्बर 1932 को गाँधी से पूना संधि करके डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्र की एकता को और मजबूत किया। 24 सितम्बर 1932 को सर तेज बहादुर सप्रू ने गांधी और डॉ. अम्बेडकर से मिलकर एक समझौता तैयार किया जिसमें डॉ. अम्बेडकर को पृथक निर्वाचन की मांग को वापस लेना था और गाँधी जी के दलितों को केन्द्रीय और राज्यों की विधान सभाओं एवं स्थानीय संस्थाओं में दलितों की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व देना एवं सरकारी नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व देना था। इसके अलावा शैक्षिक संस्थाओं में दलितों को विशेष सुविधाएं देना भी था। दोनों नेता इस समझौते पर सहमत हो गये। 24 सितम्बर 1932 को इस समझौते पर गाँधी जी और डॉ. अम्बेडकर ने तथा इनके सभी समर्थकों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते को 'पूना पैक्ट' कहा गया। पूना पैक्ट में ही दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था उनके उन्नति की आधारशिला बनी। ■

बेंगलुरु में भाजपा पार्षद 'किथागनहल्ली वासु' की हत्या

भाजपा पार्षद एवं दलित नेता श्रीनिवास प्रसाद की अज्ञात हमलावरों ने 23 मार्च को बेंगलुरु में हत्या कर दी। इनका लोकप्रिय नाम 'किथागनहल्ली वासु' था। बेंगलुर (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक श्री विनीत सिंह ने बताया, "किथागनहल्ली वासु के नाम से चर्चित भाजपा पार्षद एवं दलित नेता श्रीनिवास प्रसाद की सुबह करीब पांच बजे धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई।" गौरतलब है कि बेंगलुरु में पिछले साल अक्तूबर में भी एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गयी थी, जिसके बाद भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर राज्य में विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले पर कर्नाटक में आरएसएस के मीडिया समन्वयक श्री राजेश पदमार ने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की राजनीतिक रूप से प्रेरित हत्याएं रोकने के लिये कड़े कदम उठाने चाहिये। उन्होंने मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग भी की।

श्री राजेश पदमार ने कहा कि पिछले दो सालों में आरएसएस-विहिप-भाजपा के 10 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या की गयी है। यह लोकतांत्रिक शासन में एक खतरनाक घटनाक्रम है। उन्होंने कहा

कि 'वासु' मृदु भाषी व्यक्ति थे। हाल के दिनों में केरल में भी कुछ इसी तरह की राजनीतिक हत्याओं के मामले देखने में आ रहे थे। हाल ही में कन्नूर मंडल के भाजपा उपाध्यक्ष श्री सुशील की हत्या का मामला सामने आया था। ■

मणिपुर में नई उम्मीद

मणिपुर के नए मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह ने विधानसभा में विश्वासमत हासिल कर लिया। लेकिन इसके पहले ही उन्होंने अपने राज्य के वासियों को ऐसी खबर दी, जिससे उन्हें गहरी राहत मिली। राज्य की नगा संगठनों द्वारा 139 दिन से जारी नाकेबंदी समाप्त हो गई है। गुजरे वर्षों में नगा समुदाय और राज्य की बाकी आबादी के बीच अविश्वास की खाई लगातार चौड़ी हुई। इसी का ताजा नतीजा पिछले एक नवंबर को शुरू हुई नाकेबंदी थी। इसके कारण राज्य के लोगों को बेहद मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रसोई गैस से लेकर पेट्रोल-डीजल एवं अन्य कई आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो गई, फलस्वरूप इनके दाम आसमान छूने लगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें इतनी महंगी हो गईं, जिसके बारे में शेष भारत में सोचना भी कठिन है।

लेकिन अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का वहां के लोगों को तुरंत लाभ मिला है। नाकेबंदी खत्म कराने में केंद्र सरकार ने भी अहम भूमिका निभाई। इसे केंद्र और राज्य में एक ही दल के सत्ता में होने का फायदा भी कहा जा सकता है। फिर भाजपा के नगालैंड की अधिकांश पार्टियों के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं। इसका असर भी हुआ। हालिया विधानसभा चुनाव में नगा समुदाय के दल नगा पीपुल्स फ्रंट को चार सीटें मिलीं, जो अब बिरेन सिंह मंत्रिमंडल को समर्थन दे रहा है।

तो कहा जा सकता है कि इन नए सियासी हालात से नाकेबंदी खत्म कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ। नाकेबंदी यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) ने लगाई थी। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 37 को जाम कर दिया गया। ताजा समझौते के अनुसार यूएनसी के तमाम गिरफ्तार नेता बिना शर्त रिहा किए जाएंगे। नगा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। यूएनसी ने नाकेबंदी मणिपुर के नगा बहुल इलाकों में सात नए जिले बनाने के विरोध में लगाई थी। नए जिले बनाने का फैसला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने लिया था। नगा संगठनों ने माना कि ऐसा कर मणिपुर सरकार राज्य के नगा बहुल क्षेत्रों पर अपना स्थायी दावा जता रही है। यूएनसी उन इलाकों को बृहत्तर नगालैंड का हिस्सा मानती है। वह इन क्षेत्रों के नगालैंड में शामिल किए जाने की पक्षधर है।

बहरहाल, गौरतलब है कि इस मूल विवाद के बारे में नए समझौते में कुछ नहीं कहा गया है। मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने भी कहा कि यह मणिपुर के विकास का आगाज भर है। यानी आगे और बेहतर खबरें राज्य के लोगों को मिलेंगी। बेशक इससे मणिपुर में उम्मीद का मौहाल बनेगा। फिर भी यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अन्य मणिपुरवासियों तथा नगा समुदाय के बीच खाई चौड़ी है। मणिपुर के विभाजन की बात आते ही वहां हिंसक माहौल बन जाता है। उधर नगा संगठन उन इलाकों पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। आशा की जानी चाहिए कि बिरेन सिंह सरकार आगे चलकर इस मसले का स्थायी हल निकालेगी। फिलहाल उसने आशाजनक शुरुआत की है। ■

(साभार - नईदुनिया, संपादकीय)

बंगाल भाजपा उत्साहित

पांच राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद बंगाल भाजपा काफी उत्साहित है। अब उसकी नजर पश्चिम बंगाल पर है। वैसे भी पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भाजपा का ग्राफ जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है उससे पश्चिम बंगाल को लेकर भाजपा कुछ उम्मीद लगाती है तो वह स्वभाविक है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। इसलिए प्रदेश भाजपा की सक्रियता भी बढ़ गई है। शाह ने प्रदेश भाजपा इकाई को आश्वस्त किया है कि वह जल्द ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर आएंगे और जिन क्षेत्रों में भाजपा का आधार है वहां वह सभा करेंगे। वह पश्चिम बंगाल में सप्ताह व्यापी दौरा करेंगे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए अब कितना महत्वपूर्ण है।

राज्य में भाजपा के तीन विधायक और दो सांसद हैं। पश्चिम बंगाल में जहां भाजपा का नाम लेने वाला भी कोई नहीं था वहां मोदी लहर में भाजपा की यह उपलब्धि कम नहीं है। साथ ही राज्य में भाजपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ कर 17 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अब यदि भाजपा राज्य में संगठन को मजबूत करने पर जोर देती है तो उसका सुफल मिलने में कोई संदेह नहीं है। यही वजह है कि तृणमूल सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा को लेकर कुछ ज्यादा ही सशंकित हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कोलकाता से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। ममता सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार का हर कदम उल्टे आरएसएस के पक्ष में ही गया। सरकार ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कोलकाता में सभा करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश पर वह सभा करने में सफल हो गए। अब सरकार आरएसएस संचालित स्कूलों पर अंकुश लगाना चाहती है ताकि उसकी विचारधारा न फैले। पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक आरएसएस ने भाजपा के लिए राह आसान कर दी है। मणिपुर में तो आखिर भाजपा का भगवा लहरा ही गया जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस हतोत्साहित है। अब भाजपा पश्चिम बंगाल में संगठन के विस्तार को लेकर आगे बढ़ती है तो यह उसका सकारात्मक पक्ष होगा। ■

(साभार - दैनिक जागरण, संपादकीय)

मणिपुर में पहली बार भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अप्रत्याशित सफलता अर्जित की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को मणिपुर का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। मणिपुर में भाजपा की चुनावी रणनीति और अनेक मुद्दे पर 'कमल संदेश' के एसोसिएट एडिटर 'विकास आनंद' ने उनसे विस्तार से चर्चा की। साक्षात्कार के दौरान श्री जावडेकर ने कहा कि मोदी जी की कार्यशैली से मणिपुर के लोगों को ऐसा लगने लगा कि केन्द्र में जैसी मोदी जी की सरकार है वैसी ही मणिपुर में भी चाहिए, तभी मणिपुर का विकास संभव होगा। अपने सुधी पाठकों के लिए हम यहां पर साक्षात्कार के प्रमुख अंश को प्रकाशित कर रहे हैं।

मणिपुर के विकास के लिए भाजपा सरकार अथक परिश्रम करेगी : प्रकाश जावडेकर

मणिपुर में भाजपा की सरकार बनने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।

आपके द्वारा मणिपुर की दी हुई बधाई मैं मणिपुर के सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं, क्योंकि यह जनादेश मणिपुर की जनता ने दी है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिली है।

पिछले विधानसभा में भाजपा के पास मात्र 2 सीटें थीं, वह भी उपचुनाव में भाजपा जीती थी। जिसमें एक विधायक भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। आज भाजपा ने वहां अपनी सरकार बना ली और मणिपुर में सबसे अधिक वोट शेयर वाली पार्टी है। इतना बड़ा बदलाव कैसे संभव हुआ? चुनाव के क्या मुख्य मुद्दे थे?

भाजपा का 2012 के चुनाव में भी मैं प्रभारी था और इस बार भी प्रभारी था। तो मैंने ये देखा कि एकदम सीन कैसे बदला। सीन बदलने में जो बदलाव हुआ उसका मूल कारण मोदी जी का सुशासन लोगों को भाया। लोकसभा में हमें जितने वोट मिलते थे उतने ही मिले, लेकिन जब हमारी सरकार केन्द्र में बनी और खासकर, तीन-चार चीजें मणिपुर की जनता को भा गयी। वहां हमेशा गैस की किल्लत रहती थी। ब्लैक मार्किट में 1500 रुपए तक गैस मिलती थी। हमारी सरकार आते ही गैस की सप्लाई नियमित हो गयी। केरोसीन और पेट्रोल की सप्लाई नियमित हो गयी। सब अपनी वास्तविक कीमत में गैस मिलने लगी। इससे लोगों को बहुत राहत हुई। दूसरी ओर 5 रुपए 60 पैसे में जो चावल मिलता था, 3 रुपए में देने की योजना लाई गई। अमल में जो दिक्कते थीं वह राज्य सरकार के कारण थीं। लेकिन लोग मोदी जी के इस घोषणा पर खुश थे। तीसरा, मणिपुर के विकास के लिए केन्द्र के सभी मंत्रालयों द्वारा योजना बनाकर जो काम किया गया। उसका भी प्रभाव पड़ा और चौथा कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो गया था।

तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई जैसे छिट-पुट विरोध करने वाली पार्टियां थी। अब इन पर लोगों पर विश्वास नहीं था। भाजपा के पक्ष में लोग ऐसे लामबंद हुए कि नगरपालिका चुनाव में भी भाजपा को जीत मिली। दो उपचुनाव विधानसभा के हुए उसमें लोगों ने भाजपा को जिताया। इस कारण जनता का पूरा मूड ही बदल गया। मोदी जी के कार्यशैली से ऐसा लगने लगा कि जैसे केन्द्र में मोदी जी की सरकार है, वैसा ही मणिपुर में चाहिए। तभी मणिपुर का विकास होगा। दूसरी चीज जो लोगों को अच्छी लगी वह दो हाइवे हैं। चूंकि मणिपुर लैण्डलॉक्ड स्टेट है। लैण्डलॉक्ड होने के कारण वहां दूसरी कोई यातायात का साधन नहीं था। दूसरा विकल्प केवल हवाई है।

इसलिए दोनों हाइवे के लिए नितिन जी ने 22000 करोड़ का आवंटन किया, ताकि अच्छी सड़क के निर्माण के साथ-साथ अलग सड़क का भी निर्माण हो सके। इसका उद्घाटन भी किया। साथ ही रेलवे प्रत्यक्ष रूप से 15 किलोमीटर तक मणिपुर में आ गयी। जहां अब माल ढुलाई शुरू हुई है। और 2 साल में इम्फाल तक आएगी। आजादी के 70 साल बाद भी इम्फाल जैसे जगह पर सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को ही पानी मिलता है। वह भी सप्ताह में एक बार। ये सब किल्लतें दूर करने की हमने योजना बनाई।

नागा परिषद द्वारा आर्थिक ब्लॉकेड किया गया था, जिससे आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल बन्द हो गयी। कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश कहकर मणिपुर की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। इस अफवाह का भाजपा ने कैसे प्रतिरोध किया?

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मणिपुर के क्षेत्रीय अखण्डता से कोई समझौता नहीं होगा और शाह जी ने दिल्ली से घोषणा की कि 'बन्द फ्री, ब्लॉकैड-फी, करप्शन-फ्री' मणिपुर। उसके बाद मोदी जी की सभा हुई जिस पर आतंकवादी संगठनों ने पूरा बैन लगाया था, टोटल शट-डाऊन किया था। इसके बावजूद मोदी जी की सभा में लाखों लोग आए। इस तरह से लोगों ने ही आतंकवादियों की धमकी का जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी ने रैली में एक बात बताई, पहले सरकार यहां 10 प्रतिशत की कही जाती थी, अब जीरो परसेंट की सरकार होगी। 100 प्रतिशत काम जीरो प्रतिशत कमीशन। इसलिए मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में कुशल संगठन और सभी को जोड़ने का प्रयास, जिसका परिणाम मणिपुर में आज हमारी सरकार है।

दूसरी अफवाह थी कि NSCN (IM) फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ। इसको भी प्रादेशिक अखंडता के खिलाफ बताकर अफवाहें फैलाई गयी?

फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बारे में विस्तृत कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे। इबोबी सिंह ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बारे में अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, क्योंकि इबोबी सिंह की राजनीति इसी तरह की होती है। उनका प्रयास रहता है कि चुनाव के पहले नागा-कुकी और मैतियों को लड़ाया। लोग कहते हैं कि आर्थिक ब्लॉकेड के लिए भी वे जिम्मेवार थे। इसमें उनका हाथ था। उन्होंने ब्लॉकेड कराया और उसके खिलाफ मैती लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसका नतीजा हिंसा और आगजनी में हुई। तब हमने लोगों को बताया कि टैरिटोरियल इंटीग्रीटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बाद में मोदी जी ने भी घोषणा की, फिर लोगों को विश्वास हो गया और हमें जनसमर्थन मिला। जिसका परिणाम वहां हमारी सरकार बनी। पूर्वोत्तर में मणिपुर राजग का पांचवा राज्य है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम और मणिपुर में भाजपा और राजग की सरकारें हैं अगला लक्ष्य मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, तब पूरा पूर्वोत्तर भाजपा के पक्ष में आ जाएगा।

> *मणिपुर के विकास के लिए केन्द्र के सभी मंत्रालयों द्वारा योजना बनाकर जो काम किया गया। उसका भी प्रभाव पड़ा और दूसरा कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो गया था। तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई जैसे छिट-पुट विरोध करने वाली पार्टियां थी। अब इन पर लोगों पर विश्वास नहीं था। भाजपा के पक्ष में लोग ऐसे लामबंद हुए कि नगरपालिका चुनाव में भी भाजपा को जीत मिली।*

क्या AFSPA चुनावी मुद्दा था?

AFSPA का मुद्दा यहां नहीं था। चूंकि हमने कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा रोजगार मुहैया कराने का वादा किया था, इसलिए लोगों ने हमें वोट दिया। मणिपुर छोटा राज्य है, लेकिन मणिपुर की जीत हमारे लिए बहुत अहम है। जिन दलों ने हमारा साथ दिया है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं। ■

संगठनात्मक नियुक्तियां

दिल्ली के तीनों नगर निगम के मतदान 23 अप्रैल को होंगे और 26 अप्रैल को मतगणना होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 17 मार्च को चुनावों की देखरेख हेतु श्री विनय सहस्रबुद्धे, सांसद एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्रीमती निर्मला सीतारमन, केन्द्रीय मंत्री, डॉ.जितेन्द्र सिंह, केंद्रीय मंत्री एवं श्री संजीव बालियान, केन्द्रीय मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू दिल्ली प्रदेश के प्रभारी के रूप में कार्यरत रहेंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देश को स्वस्थ और मजबूत बनाएगी

हमने उच्च किस्म की ऐसी दवाईयां बनाई हैं जिन्हें पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में सप्लाई की जाने वाली जेनेरिक दवाओं का लगभग 20 प्रतिशत भारत में निर्मित होता है। हालांकि हमें इस बात पर गर्व है, लेकिन हम यह भी हम जानते हैं कि इससे भी अधिक बेहतर हम कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर हमारा खर्च कम हो सकता है, जिससे नागरिकों को वित्तीय संकट से बचाया जा सकता है। हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जहां प्रत्येक नागरिक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सकता है।

| जगत प्रकाश नड्डा |

विगत दस वर्षों से भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस विशाल देश में प्रत्येक बच्चे को रोगमुक्त करने के लिए पोलियो वेक्सीन की बहुआयामी खुराकें दी गई हैं। पूरे राष्ट्र में हमारी शिशु और मातृत्व मृत्यु दर में एक-तिहाई से भी कहीं अधिक गिरावट आई है। हमने उच्च किस्म की ऐसी दवाईयां बनाई हैं जिन्हें पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में सप्लाई की जाने वाली जेनेरिक दवाओं का लगभग 20 प्रतिशत भारत में निर्मित होता है। हालांकि हमें इस बात पर गर्व है, लेकिन हम यह भी हम जानते हैं कि इससे भी अधिक बेहतर हम कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर हमारा खर्च कम हो सकता है, जिससे नागरिकों को वित्तीय संकट से बचाया जा सकता है। हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जहां प्रत्येक नागरिक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सकता है।

> राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य सभी को, विशेष रूप से वंचित लोगों तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सके।

राज्य सरकारों और अन्य लोगों के साथ विचार-विमर्श कर हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में धन की उपलब्धता बढ़ाई है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए बीमारियों की रोकथाम का प्रबंध किया है। हमने तकनीक और मानव संसाधनों का बेहतर प्रयोग किया है। विभिन्न स्वास्थ्य पद्धतियों को प्रोत्साहित किया है ताकि हम बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सकें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य सभी को, विशेष रूप से वंचित लोगों तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सके।

सौभाग्य से, हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है जिससे हम

स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बना सकते हैं। हम मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बना कर ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाने में समर्थ हो गए हैं, जिससे हम सभी को स्वास्थ्य मुहैया कराने की स्थिति पैदा कर सकें। हमने चार तरह के निवेशों को प्राथमिकता दी है, जिनके जरिए हम भविष्य के लिए भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।

सबसे पहले हमारा ध्यान बीमारियों की रोकथाम कर बेहतर स्वास्थ्य को प्रोन्नत करना है। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी को व्यापक व गुणवापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। हमारा जोर रूग्णता देखभाल की बजाय आरोग्यता पर है। 'स्वस्थ नागरिक अभियान' के अन्तर्गत लोक अभियान की शुरूआत की गई है ताकि लोग स्वस्थ रहें और उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत ही न हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम चुनिंदा प्राइमरी हैल्थकेयर सेवाओं से अपना ध्यान हटाकर टू वे रेफरल की तरफ ले जाएं जिसमें एनसीडी, मेंटल हैल्थ आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की मुख्य बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को धीरे-धीरे जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक ले जाएं। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर दो-तिहाई या इससे अधिक के आवंटन का निर्णय किया गया है।

इस नीति का दूसरा मुख्य उद्देश्य स्वास्थ व्यवस्था को मजबूत करने पर है, ताकी सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके और लोगों को जरूरी निःशुल्क दवाएं, रोग निदान और सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं प्राप्त हो सके। 'गोल्डन समय'में माताओं और बच्चों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना भी है कि देश के सभी हिस्सों में प्रति 10 लाख आबादी पर 2000 बिस्तरों की व्यवस्था हो।

हमारा तीसरा स्तम्भ नागरिकों का शक्तिकरण और उत्तम प्रकार का रोगी उपचार है। ऐसे उपाय किए जाएंगे ताकि अस्पतालों को समय-समय पर गुणवत्ता स्तर को प्रमाणित करना पड़े। नीति में सिफारिश की गई है कि सभी विवादों के समाधान के लिए तंत्र स्थापित किया जाए और उनके लिए आदर्श दिशा-निर्देश और प्रारूपों पर आधारित प्रमाण तैयार किए जाएं। सरकारी अस्पतालां में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विभिन्न प्रकार के रोगियों को संसाधनों का उचित लाभ मिले।

'गोल्डन समय'में माताओं और बच्चों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना भी है कि देश के सभी हिस्सों में प्रति 10 लाख आबादी पर 2000 बिस्तरों की व्यवस्था हो।

हमारी स्वास्थ्य नीति का चौथा स्तम्भ भारत की इनोवेशन पॉवर, टेक्नालॉजी और आइसीटी क्षमता को बेहतर बनाना है। पॉलिसी में कहा गया है कि स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग पर अधिक ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे नागरिकों को अधिक कारगर स्वास्थ्य का लाभ मिल सके और साथ ही साथ रोजगार सृजन भी हो सके। पॉलिसी में फेडरल हैल्थ इंफार्मेशन आर्किटेक्चर की स्थापना की बात कही गई है जो एमडीडीएस के साथ संगत बैठती है। इसके अलावा विशेष रूप से कुछ राज्यों में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए मेडिकल कालेजों के जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया गया है। अन्य सुविधाओं ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि दूरदराज के इलाकों तक पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बन सके। इस नीति में क्षमता तथा ज्ञान विस्तार के लिए दूर-शिक्षा, नेशनल नॉलिज नेटवर्क, टेली-सीएमई, टेली-विचार विमर्श और डिजिटल पुस्तकालय तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रावधान रखा गया है।

मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन से संबंधित समुचित लक्ष्य रखे गए हैं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। यही नहीं, भारत सरकार सभी व्यक्तियों के भावी स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध है। सभी लोगों के लिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु सरकार की भूमिका को प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की घोषणा की है और हम राज्य सरकारों के निकट सहयोग के साथ इसे कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसे समयबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा ताकि सभी भारतीय पूरी तरह स्वस्थ रहे और अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकें। ■

(लेखक केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं।)

देवभूमि, देवभूमि रहे, इसे हम सुनिश्चित करेंगे : श्याम जाजू

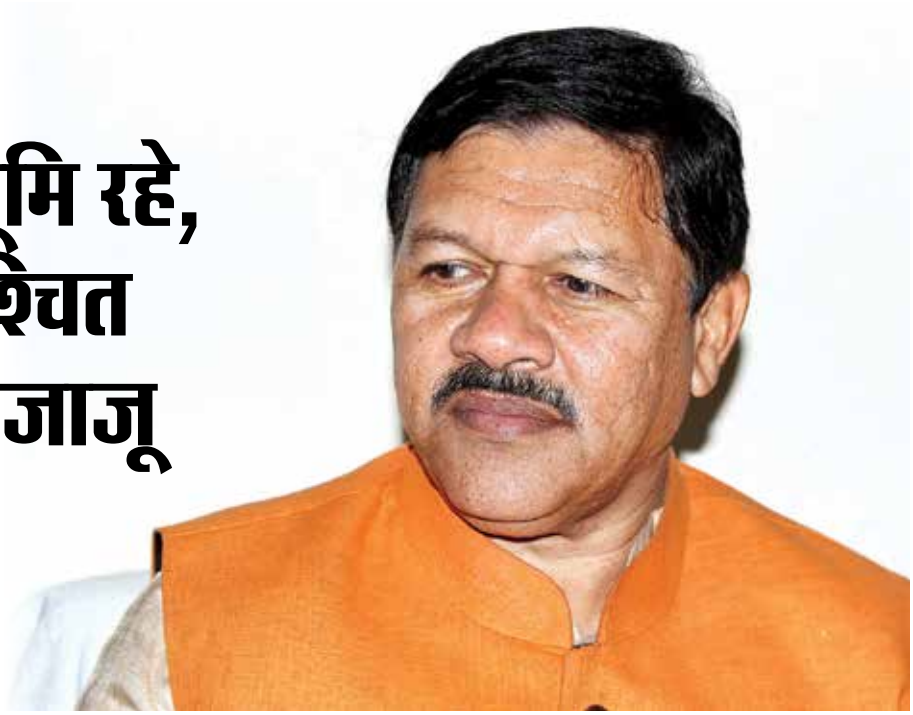

हाल ही में संपन्न उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए यहां अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भाजपा ने राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटों पर जीत का परचम लहराया। यह राज्य में अब तक के इतिहास में न केवल भाजपा, बल्कि किसी भी दल के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है।

विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी श्री श्याम जाजू से कमल संदेश के सहायक संपादक संजीव कुमार सिन्हा ने बातचीत की। श्री जाजू ने भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकताएं हैं– उत्तराखंड से हो रहे पलायन को रोकना, पर्यटन स्थलों को विकसित करना, गांवों तक सड़क मार्ग बनाना, गंगा की स्वच्छता व निर्मलता के लिए ठोस पहल करना। प्रस्तुत है बातचीत के मुख्यांश–

उत्तराखंड में भाजपा की भारी जीत हुई है। इसके पीछे क्या कारण रहे?

उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। पार्टी को एकतरफा जनादेश मिला है। अस्थिरता के दौर से उत्तराखंड निकलकर स्थिरता की ओर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत है। जीत की दर 82 प्रतिशत है, ऐसा यह पहला प्रदेश है। लोकसभा के चुनाव में भी गुजरात के बाद तुरंत दूसरा नंबर मत प्रतिशत देने में उत्तराखंड का रहा था। सभी के सभी लोकसभा प्रत्याशी हमारे जीते थे। विधानसभा में हुई इस जीत का श्रेय अगर किसी को देना होगा तो वह हैं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी जी और जिनकी रणनीति काम में आई वह हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह उनका व्यक्तिगत ध्यान इस चुनाव पर था। कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते कार्यकर्ताओं के अपार परिश्रम से अध्यक्षजी द्वारा बनाई हुई रणनीति हम कार्यान्वित कर सके।

भाजपा ने चुनाव को लेकर क्या योजनाएं बनाई थी?

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का विशेष लगाव उत्तराखंड से है। यह देवभूमि और वीरभूमि के रूप में जाना जाता है। नरेन्द्र मोदी जी ने, सरकार किसकी है ऐसा विचार न करते हुए पहली बार 17,000 करोड़ रुपए रेल के लिए दिए। 12,000 करोड़ रुपए चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के लिए दिए। 'वन रैंक-वन पेंशन' का मुद्दा उन्होंने हल किया। इन सबका स्वाभाविक असर पूरे उत्तराखंड में है। चुनाव-प्रचार के दौरान नरेन्द्र मोदी जी ने वहां पर चार जनसभाओं को संबोधित किया। अमित शाह जी ने अनेक जनसभाओं को संबोधित किया। हमारे पार्टी नेता राजनाथ सिंह जी, थावरचंद गेहलोत जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, स्मृति ईरानी जी सहित अनेक नेताओं ने चुनाव-प्रचार अभियान को गति प्रदान की। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री

बीसी खंडूरी जी, श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्री विजय बहुगुणा जी, इनका भी प्रमुख योगदान इसमें है और कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा अभियान चला।

चुनाव-प्रचार के दौरान भाजपा ने कौन से मुद्दे उठाए?

चुनाव-प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को हमने मुद्दा बनाया। इसके खिलाफ हमने अनेक आंदोलन चलाए। प्रदेश भर में गतिविधियां निरंतर जारी रहीं। पहले तो हमने 'पर्दाफाश रैली' की, इसके जरिए हमने उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर किए। हमारे सभी लोक प्रतिनिधियों ने घर-घर जाकर दस्तक दिए। दूसरा, 'हिसाब दो-जवाब दो' अभियान चलाया, जिसके चलते हमारा व्यापक जनसंपर्क हुआ। तीसरा, हमारे युवामोर्चा के माध्यम से हमने 'घेरा डालो-डेरा डालो' के कार्यक्रम किए। महिलाओं के कई सम्मेलन हुए। सभी 70 विधानसभाओं में अजय टम्टा जी और हमारे प्रमुख नेताओं के प्रवास हुए। अनुसूचित जाति के सम्मेलन हमने वहां पर किए। हमारी 'परिवर्तन यात्रा' को प्रदेश में बहुत यश मिला और वह चुनाव अभियान का आधार बना। इन्हीं मुद्दे के आधार पर हमें जीत हासिल हुई।

भाजपा सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं?

हमारे सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख है उत्तराखंड से होने वाला पलायन रोकना। चुनाव के दौरान नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि 'पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी' यहीं रहेगी, इसकी हम चिंता करेंगे। प्रदेश में भोले-भाले लोग रहते हैं, इसे एक एक अच्छा प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश के रूप में विकसित करना, यह अटलजी का सपना था, इस बार भी हमने नारा दिया था, 'अटल जी का काम अधूरा - नरेन्द्र मोदी करेंगे पूरा।' मुझे लगता है कि यही हमारी प्राथमिकता है। आज भी उत्तराखंड में बहुत से गांवों तक जाने वाला रोड नहीं है। प्राथमिक आरोग्य केन्द्र की समुचित व्यवस्था नहीं हैं। वहां पर डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है। प्राथमिक विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है और पहाड़ों में तो बहुत सी बातों की अव्यवस्थाएं हैं। इसलिए पहाड़ों से पलायन हो रहा है। यह पलायन रोकना है। इसके साथ, जिस पर्यटन पर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था निर्भर है, उसे प्रमोट करना, विकसित करना, देश से आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करना, ये दोनों हमारी प्राथमिकताएं वहां पर हैं।

क्या पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों की समीक्षा की जाएगी?

पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत ज्यादा कुछ निर्णय तो किए नहीं थे, सिंगल मैन आर्मी की सरकार चल रही थी, इससे असहमति जताते हुए बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ी। एक सशक्त और समर्थ विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहां पर मौजूद है।

चुनाव-प्रचार के दौरान कांग्रेस ने नोटबंदी को मुद्दा बनाया था। इस पर आपका क्या कहना है?

नोटबंदी के फैसले से पूरे देश में हमें फायदा हो रहा है। लोगों को तात्कालिक दिक्कत होने के बावजूद यह ध्यान में आया कि मोदी जी की नीति स्पष्ट है और नीयत साफ है। इसलिए गरीब-अमीर सब लोगों ने सहयोग दिया। इससे गरीबों का सम्मान बढ़ा है। पहाड़ों में तो कई गांवों तक बैंक नहीं हैं। 25-25 किलोमीटर तक लोगों को बहुत दिक्कत हुई, तो भी मोदी जी पर भरोसा रखकर लोगों ने इसको समर्थन दिया है। और उसका भी नोटबंदी पर असर हुआ है। हमारी पार्टी है गरीबों की, किसानों की। आम आदमी की चिंता करने वाली पार्टी के रूप में हमारी छवि बनी है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में दो पवित्र नदियों गंगा और यमुना को 'जीवित मानव का दर्जा' देने का आदेश दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से इस दिशा में कुछ ठोस पहल किए जाएंगे?

उच्च न्यायालय द्वारा आदेश देना अलग बात है, हमारी पार्टी के लिए प्रारंभ से ही यह श्रद्धा का विषय है। गंगा-यमुना इन्हें स्वच्छ रखना, उनकी निर्मलता को ध्यान में लेकर कार्यक्रम बनाना, यह हमारी प्रतिबद्धता का विषय है। केन्द्र में भाजपा सरकार आने के बाद तुरंत इस दिशा में स्वतंत्र मंत्रालय गठित करके उमा भारती जी के नेतृत्व में हमने 'नमामि गंगे' योजना बनाई, उसमें कई करोड़ के प्रावधान किए, उसका क्रियान्वयन चल रहा है और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस प्रकार गंगा निर्मल बहती रहनी चाहिए, लोगों की श्रद्धा उस पर है, और उसमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ये सब हमारी प्राथमिकताएं हैं। आज तक की सरकारों ने केवल घोषणाएं कीं, हम उस पर सक्रियता से काम कर रहे हैं।

प्रदेश में गोरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे?

जहां-जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ऐसे सभी विषयों पर गंभीरतापूर्वक हम क्या कर सकते हैं, इस पर अमल करते हैं। ऐसा हमने हरियाणा में किया है, महाराष्ट्र में किया है, उत्तराखंड भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। गाय पर लोगों की श्रद्धा है, उस प्रकार के बूचड़खाने वहां पर बंद होने चाहिए। कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि हरिद्वार के इर्द-गिर्द भी सामिष भोजन की व्यवस्था शुरू हो गई है, शराब सेवन शुरू हो गया है। अब प्रदेश में भाजपा सरकार है। पार्टी का एजेंडा रहेगा कि देवभूमि, देवभूमि रहे; इसे सुनिश्चित किया जाएगा। जो निषेध क्षेत्र है, उसमें सख्ती से हम पहल करेंगे। ■

खास बातें

- कांग्रेस शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को हमने मुद्दा बनाया। 'पर्दाफाश रैली' की। 'हिसाब दो-जवाब दो' अभियान चलाया। युवामोर्चा ने 'घेरा डालो-डेरा डालो' के कार्यक्रम किए। अनुसूचित जाति सम्मेलन हुए। यह चुनाव अभियान का आधार बना।
- हमारी प्राथमिकताएं- प्रदेश का संपूर्ण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सुगठित व्यवस्था बनाना, राज्य से हो रहे पलायन को रोकना, गांवों तक सड़के बनाना, पर्यटन स्थलों को विकसित करना और गंगा की स्वच्छता व निर्मलता के लिए ठोस पहल करना।

दशकों तक देश गलत दिशा में चलाः नरेंद्र मोदी

इंडिया टुडे कॉनक्लेव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अनेक दशकों तक हम गलत नीतियों के साथ गलत दिशा में चले। सब कुछ सरकार करेगी यह भाव प्रबल हो गया। कई दशकों के बाद गलती ध्यान में आई। गलती सुधारने का प्रयास हुआ औऱ सोचने की सीमा बस इतनी थी कि दो दशक पहले गलती सुधारने का एक प्रयास हुआ और उसे ही रीफॉर्म मान लिया गया।

उन्होंने कहा कि ज्यादातर समय देश ने या तो एक ही तरह की सरकार देखी या फिर मिली-जुली। उसके कारण देश को एक ही सोच या गतिविधियां नजर आई। पहले पॉलिटिकल सिस्टम से जन्मी चुनाव प्रेरित होती थी या फिर ब्यूरोक्रेसी के रिजिड फ्रेमवर्क पर आधारित थी। सरकार चलाने के यही दो सिस्टम थे और सरकार का आकलन भी इसी आधार पर होता था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें स्वीकार करना होगा कि 200 साल में तकनीक जितनी बदली, उससे ज्यादा पिछले 20 साल में बदली है। स्वीकार करना होगा कि 30 वर्ष पहले के युवा और आज के युवा की उम्मीदों में बहुत अंतर है। स्वीकार करना होगा कि दो ध्रुवीय ओर परस्पर निर्भर विश्व की सभी समीकरण बदल चुके हैं। आजादी के आंदोलन के कालखंड को देखें तो उसमें व्यक्तिगत आकांक्षा से ज्यादा राष्ट्रीय आकांक्षा था। उसकी तीव्रता इतनी थी कि उसने देश को सैकड़ों सालों की गुलामी से बाहर निकाला। अब समय की मांग है-आजादी के आंदोलन की तरह विकास का आंदोलन- जो पर्सनल एस्पीरेशन को कलेक्टिव एस्पीरेशन में विस्तार करे और कलेक्टिव एस्पीरेशन देश के सर्वांगीण विकास का हो।

उन्होंने कहा कि ये सरकार एक भारत-श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर चल रही है। समस्याओं को देखने का तरीका कैसा हो, इस पर दृष्टिकोण अलग है। बहुत साल तक देश में अंग्रेजी-हिंदी पर संघर्ष होता रहा। हिंदुस्तान की सभी भाषाएं हमारी अमानत हैं। ध्यान दिया गया कि सभी भाषाओं को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में दो-दो राज्यों की जोड़ी कराई और अब राज्य एक दूसरे की सांस्कृतिक विविधता के बारे में जान रहे हैं।

यानी चीजें बदल रही हैं और तरीका अलग है। इसलिए आपका ये शब्द इन सब बातों के लिए छोटा पड़ रहा है। ये व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने वाली सोच नहीं है। ये कायाकल्प है जिससे इस देश की आत्मा अक्षुण्ण रहे, व्यवस्थाएं समय के अनुकूल होती चलें। यही 21वीं सदी

> हमें स्वीकार करना होगा कि 200 साल में तकनीक जितनी बदली, उससे ज्यादा पिछले 20 साल में बदली है। स्वीकार करना होगा कि 30 वर्ष पहले के युवा और आज के युवा की उम्मीदों में बहुत अंतर है। स्वीकार करना होगा कि दो ध्रुवीय ओर परस्पर निर्भर विश्व की सभी समीकरण बदल चुके हैं। आजादी के आंदोलन के कालखंड को देखें तो उसमें व्यक्तिगत आकांक्षा से ज्यादा राष्ट्रीय आकांक्षा था। उसकी तीव्रता इतनी थी कि उसने देश को सैकड़ों सालों की गुलामी से बाहर निकाला।

के जनमानस का मन है। इसलिए "डिसरप्टर- इन- चीफ" अगर कोई है तो देश के सवा सौ करोड़ हिन्दुस्तानी है। जो हिंदुस्तान के जन-मन से जुड़ा है वो भली-भांति समझ जाएगा कि डिसरप्टर कौन है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बंधे-बंधाए विचार, बातों को अब भी पुराने तरीके से देखने का नजरिया ऐसा है कि कुछ लोगों को लगता है कि सत्ता के गलियारे से ही दुनिया बदलती है। ऐसा सोचना गलत है। हमने समयबद्ध इमपलिमेंटेशन और समेकित सोच को सरकार की कार्य संस्कृति के साथ जोड़ा है। काम करने का ऐसा तरीका जहां सिस्टम

में ट्रांसपेरेंसी हो, प्रक्रियाओं को नागरिकों के अनुकूल व विकास परक बनाया जाए, एफिशिएन्सी लाने के लिए प्रक्रिया re-engineer किया जाए। आज भारत दुनिया की तेजी से विकसित होती अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को दुनिया की टॉप तीन प्रॉस्पेक्टिव होस्ट इकोनोमी में आंका गया है। वर्ष 2015-16 में 55 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रिकॉर्ड निवेश हुआ। दो सालों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कम्पटीटिवनेस इन्डेक्स में भारत 32 स्थान ऊपर उठा है।

उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया आज भारत का सबसे बड़ा इनीशिएटिव बन चुका है। आज भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा मैन्यूफैक्चरिंग देश है। ये सरकार कोओपरेटिव फेडरेलिज्म पर जोर देती है। GST आज जहां तक पहुंचा है, वो डेलीबरेटिव डेमोक्रेसी का परिणाम है जिसमें हर राज्य के साथ संवाद हुआ। GST पर सहमति होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है लेकिन इसकी प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसा निर्णय है जो आम सहमति से हुआ है। सभी राज्यों ने मिलकर इसकी जिम्मेदारी ली है। आपके नजरिए से ये डिसरपटिव हो सकता है, लेकिन GST दरअसल संघीय व्यवस्था के नई ऊँचाई पर पहुंचने का सबूत है। सबका साथ-सबका विकास सिर्फ नारा नहीं है, इसे जी कर दिखाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में वर्षों से माना गया कि श्रम कानूनों विकास में बाधक हैं। दूसरी तरफ ये भी माना गया कि श्रम कानूनों में सुधार करने वाले मजदूर विराधी हैं। यानि दोनों एक्सट्रीम स्थिति थी। कभी ये नहीं सोचा गया कि इम्प्लायर, इम्प्लाई और एस्पीरेन्ट्स तीनों के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। देश में अलग-अलग श्रम कानूनों के पालन के लिए पहले एम्पलॉयर को 56 अलग-अलग रजिस्टरों में जानकारी भरनी होती थी। एक ही जानकारी बार-बार अलग-अलग रजिस्टरों में भरी जाती थी। अब पिछले महीने सरकार ने नोटिफाई किया है कि एम्पलॉयर को श्रम कानूनों के तहत 56 नहीं सिर्फ 5 रजिस्टर maintain करने होंगे। ये व्यापार को सरल करने में उद्यमियों की बड़ी मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि जॉब मार्केट के विस्तार पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के साथ ही सरकार का जोर पर्सनल सेक्टर पर भी है। मुद्रा योजना के तहत नौजवानों को बिना बैंक गारंटी कर्ज दिया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में छह करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज दिया गया है। सामान्य दुकानें और संस्थान साल में पूरे 365 दिन खुले रह सकें उसके लिए भी राज्यों को सलाह दी गई है।

पहली बार कौशल विकास मंत्रालय बनाकर इस पर पूरी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और इनकम टैक्स में छूट के माध्यम से स्थायी रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह अप्रेन्टिसशिपएक्ट में सुधार करके अप्रेन्टिसों की संख्या बढ़ाई गई है और अप्रेन्टिस के दौरान मिलने वाले स्टाईपेंड में भी बढ़ोतरी की गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की शक्ति से जनशक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि बिना देश के लोगों को जोड़े, इतना बड़ा देश चलाना संभव नहीं है। बिना देश की जनशक्ति को साथ लिए आगे बढ़ना संभव नहीं है। दीवाली के बाद कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद आप सभी ने जनशक्ति का ऐसा उदाहरण देखा है, जो युद्ध के समय अथवा संकट के समय ही दिखता है। ये जनशक्ति इसलिए एकजुट हो रही है, क्योंकि लोग अपने देश के भीतर व्याप्त बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं, कमजोरियों को हराकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नया भारत बनाना चाहते हैं।

अगर आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, 100 से ज्यादा जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए हैं तो ये इसी जनशक्ति की एकजुटता का प्रमाण है। अगर एक करोड़ से ज्यादा लोग गैस सब्सिडी का फायदा उठाने से खुद इनकार कर रहे हैं तो ये इसी जनशक्ति का उदाहरण है। इसलिए आवश्यक है कि जनभावनाओं का सम्मान हो और जनआकांक्षाओं को समझते हुए देशहित में फैसले लिए जाएं और उन्हें समय पर पूरा किया जाए।

अगर आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, 100 से ज्यादा जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए हैं तो ये इसी जनशक्ति की एकजुटता का प्रमाण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकार ने जनधन योजना शुरू की तो कहा था कि देश के गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ेंगे। इस योजना के तहत अब तक 27 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। इसी तरह सरकार ने लक्ष्य रखा कि तीन वर्ष में देश के 5 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देंगे। सिर्फ 10 महीने में ही लगभग दो करोड़ गरीबों को गैस कनेक्शन दिए भी जा चुके हैं। सरकार ने कहा था एक हजार दिन में उन 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे, जहां आजादी के 70 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची। लगभग 650 दिन में ही 12 हजार से ज्यादा गांवों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है।

जहां नियम-कानून बदलने की जरूरत थी, वहां बदले गए और जहां समाप्त करने की जरूरत थी, वहां समाप्त किए गए। अब तक 1100 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया जा चुका है। सालों तक देश में बजट शाम को 5 बजे पेश होता था। ये व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी क्योंकि भारत में शाम का 5 बजे ब्रिटेन के हिसाब से सुबह का साढ़े 11 बजे होता था। अटल जी ने इसमें बदलाव किया।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष आपने देखा है कि बजट को एक महीना पहले पेश किया गया। इम्पलिमेंटेशन की दृष्टि से ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। वरना इससे पहले फरवरी के आखिर में बजट आता था और विभागों तक पैसे पहुंचने में महीनों निकल जाते थे। फिर इसके

बाद मॉनसून की वजह से काम में और देरी होती थी। अब विभागों को उनकी योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि समय पर मिल जाएगी। इसी तरह बजट में योजना, गैर-योजना का कृत्रिम विभाजन था। सुर्खियों में आने के लिए नई- नई चीजों पर जोर दिया जाता था और जो पहले से चला आ रहा है, उसे नजरअंदाज किया जाता था। इस वजह से धरातल पर बहुत असंतुलन था। इस कृत्रिम विभाग को खत्म करके हमने बहुत बड़ा बदलाव करने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि इस बार आम बजट में रेलवे बजट का भी विलय किया गया। अलग से रेल बजट पेश करने की व्यवस्था भी अंग्रेजों की ही बनाई हुई थी। अब ट्रांसपोर्ट के आयाम बहुत बदल चुके हैं। रेल है, रोड है, एविएशन है, वॉटर वे, समुद्री मार्ग है, इन सभी पर समेकित तरीके से सोचना आवश्यक है। सरकार का ये कदम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजीकल रीवोल्यूशन का आधार बनेगा। पिछले ढाई वर्षों में आपने सरकार की नीति-निर्णय और नीयत, तीनों देखी है। मैं मानता हूं नए भारत के लिए यही एप्रोच 21वीं सदी में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, नए भारत की नींव और मजबूत करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहां ज्यादातर सरकारों की एप्रोच रही है- दीए जलाना, रिबन काटना, और इसे भी कार्य ही माना गया, कोई इसे बुरा भी नहीं मानता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 1500 से ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हुईं लेकिन वो सिर्फ फाइलों में ही दबे रहे। ऐसे ही कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बरसों से अटके हुए हैं। अब परियोजनाओं की उचित निगरानी के लिए एक व्यवस्था विकसित की गई है- "प्रगति" यानि Pro-Active Governance and Timely Implementation प्रधानमंत्री कार्यालय में मैं बैठता हूं और सारे केंद्रीय विभागों के सचिव, सारे राज्यों के चीफ सेक्रेट्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हैं। जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनकी पहले से ही एक लिस्ट तैयार की जाती है।

अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति की बैठकों में हो चुकी है। देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण 150 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट, जो बरसों से अटके हुए थे, उनमें अब तेजी आई है। देश के लिए नई पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस है। पिछले 3 बजट में रेल और रोड सेक्टर को सर्वाधिक पैसा दिया गया है। उनके काम करने की क्षमता बढ़ाने पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि रेल और रोड, दोनों ही सेक्टर में काम करने की जो औसत गति थी, उसमें काफी बढोतरी हुई है।

उन्होंने कहा कि पहले रेलवे के विद्युतिकरण का काम धीमी गति से चलता था। सरकार ने रेलवे के रूट इलेक्ट्रिफिकेशन कार्यक्रम को गति दी। इससे रेल के चलाने के खर्च में कमी आई और देश में ही उपलब्ध बिजली का उपयोग हुआ। इसी तरह रेलवे को Electricity Act के अंतर्गत ओपेन एसेस की सुविधा दी गई। इस कारण से रेलवे द्वारा खरीदी जा रही बिजली के ऊपर भी रेलवे को बचत हो रही है। पहले बिजली वितरण कंपनियां इसका विरोध करती थीं जिससे रेलवे को उनसे मजबूरन महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ती थी। अब रेलवे कम दाम पर बिजली खरीद सकती है।

पहले पावर प्लांट और कोयले की लिन्केज इस तरीके से थी कि अगर प्लांट उत्तर में है तो कोयला मध्य भारत से आएगा और उत्तर या पूर्व भारत से कोयला पश्चिम भारत में जाएगा। इस कारण पावर प्लांट को कोयले के ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था और बिजली महंगी होती थी। हमने कोल लिंकेज का रेशनलाइजेशन किया जिससे ट्रांसपोर्टेशन खर्च और समय दोनों में कमी आई और बिजली सस्ती हुई।

ये दोनों उदाहरण बताते हैं कि ये सरकार टनेल विजन नहीं, टोटल विजन को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। जैसे रेलवे ट्रैक के नीचे से सड़क ले जाने के लिए रेल ओवर ब्रिज बनाने के लिए महीनों तक रेलवे से ही स्वीकृति नहीं मिलती थी। महीनों तक इसी बात पर माथापच्ची चलती थी कि रेल ओवर ब्रिज का डिजाइन क्या हो। अब इस सरकार में रेल ओवर ब्रिज के लिए यूनिफार्म डिजाइन बनाई गई है और प्रपोजल इस डिजाइन के आधार पर होता है तो तुरंत NOC दे दी जाती है।

बिजली उपलब्धता देश के आर्थिक विकास की पूंजी है। जब से हमारी सरकार आई है, हम पावर सेक्टर पर होलिस्टिकली काम कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। 46 हजार मेगावॉट की जनरेशन कपैसिटी को जोड़ा गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजली उपलब्धता देश के आर्थिक विकास की पूंजी है। जब से हमारी सरकार आई है, हम पावर सेक्टर पर होलिस्टिकली काम कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। 46 हजार मेगावॉट की जनरेशन कपैसिटी को जोड़ा गया है। जनरैशन कपैसिटी करीब 25 प्रतिशत बढ़ी है। कोयले का ट्रांसपेरेंट रूप से ऑक्शन करना और पावर प्लांट को कोयला उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता रही है। आज ऐसा कोई थर्मल प्लांट नहीं है, जो कोयले की उपलब्धता की दृष्टि से क्रिटिकल हो। क्रिटिकल यानि, कोयले की उपलब्धता 7 दिन से कम की होना। एक समय बड़ी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि देश में बिजली संकट गहरा गया है- पावर प्लांट के पास कोयला खत्म हो रहा है। पिछली बार कब ये वाली ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी? आपको याद नहीं होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज अब आपके आर्काइव में पड़ी होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के पहले दो सालों में 50 हजार सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बनाई गईं। जबकि 2013-14 में 16 हजार सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई थीं। सरकारी बिजली डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को हमारी उदय स्कीम द्वारा एक नया जीवन मिला है। इन सभी कामों से बिजली की उपलब्धता बढ़ी है और कीमत भी कम हुई है।

आज एक App – विद्युत प्रवाह - के माध्यम से देखा जा सकता है कि कितनी बिजली, कितनी कीमत पर उपलब्ध है। सरकार स्वच्छ ऊर्जा पर भी जोर दे रही है। लक्ष्य 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा के

उत्पादन का है जिसमें से अब तक 50 गीगावॉट यानी पचास हजार मेगावॉट क्षमता हासिल कर ली गई है।

भारत ग्लोबल विंड पावर ट्रस्टाल्ड कैपीसिटी के मामले में विश्व में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। सरकार का जोर बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बिजली की खपत कम करने पर भी है। देश में अब तक लगभग 22 करोड़ LED बल्ब बांटे जा चुके हैं। इससे बिजली की खपत में कमी आई है, प्रदूषण में कमी आई है और लोगों को 11 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की अनुमानित बचत हो रही है।

उन्होंने कहा कि देश भर की ढाई लाख पंयाचतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए 2011 में काम शुरू किया गया था। लेकिन 2011 से 2014 के बीच सिर्फ 59 ग्राम पंचायतों तक ही ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली गई थी। इस रफ्तार से ढाई लाख पंचायतें कब जुडतीं, आप अंदाजा लगे सकते हैं। सरकार ने प्रक्रिया में जरूरी बदलाव किए, जो समस्याएं थीं, उन्हें दूर करने का मेकेनिज्म तैयार किया।

पिछले ढाई वर्षों में 76 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। साथ ही अब हर ग्राम पंचायत में wifi hot-spot देने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि गांव के लोगों को आसानी से ये सुविधा मिल सके। ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन तक भी ये सुविधा पहुंचे। साधन वहीं हैं, संसाधन वही हैं, लेकिन काम करने का तरीका बदल रहा है, रफ्तार बढ़ रही है। 2014 से पहले एक कंपनी को इनकारपोरेट करने में 15 दिन लगते थे, अब सिर्फ 24 घंटे लगते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले इनकम टैक्स रिफंड आने में महीनों लग जाते थे, अब कुछ हफ्ते में आ जाता है। पहले पासपोर्ट बनने में भी कई महीने लग जाते थे, अब एक हफ्ते में पासपोर्ट आपके घर पर होता है। हमारे लिए तकनीक, सुशासन के लिए सहायक तो है ही गरीबों के सशक्तिकरण के लिए भी है। सरकार देश के किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से काम कर रही है।

इसके लिए बीज से लेकर बाजार तक सरकार हर स्तर पर किसान के साथ खड़ी है। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जा रहे हैं, हर खेत तक पानी देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऐसे रिस्क कवर किए गए हैं जो पहले नहीं होते थे। इसके अलावा किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, यूरिया की किल्लत अब पुरानी बात हो गई है।

किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिले इसके लिए e-NAM योजना के तहत देशभर की 580 से ज्यादा मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। स्टोरेज और सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में भी हर स्तर पर काम किया जा रहा है। बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रीवेन्टिव हेल्थकेयर, स्वच्छता, इन सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू की गई हैं। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को स्वीकृति दी है। एक रोडमैप तैयार किया गया है जिससे हेल्थकेयर सिस्टम को देश के हर नागरिक के लिए सुलभ बनाया जाएगा।

सरकार इस कोशिश में हैं कि आने वाले समय में देश की GDP का कम से कम ढाई प्रतिशत स्वास्थ्य पर ही खर्च हो। आज देश में 70 प्रतिशत से ज्यादा मेडिकल डिवाइस और उपकरण विदेश से आता है। अब प्रयास है कि मेक इन इंडिया के तहत लोकल मैनुफेक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए ताकि इलाज और सस्ता हो।

उन्होंने कहा कि सरकार का जोर सोशल इनफ्रास्टकचर पर भी है। हमारी सरकार दिव्यांग जनों के लिए सेवा भाव से काम कर रही है। देश भर में लगभग 5 हजार कैंप लगाकर 6 लाख से ज्यादा दिव्यांगों को आवश्यक सहायता उपकरण दिए गए हैं। ये कैंप गिनीज बुक तक में दर्ज हो रहे हैं। अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, सरकारी दफ्तरों में चढ़ते या उतरते वक्त दिव्यांग जनों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है।

सरकार का जोर सोशल इनफ्रास्टकचर पर भी है। हमारी सरकार दिव्यांग जनों के लिए सेवा भाव से काम कर रही है। देश भर में लगभग 5 हजार कैंप लगाकर 6 लाख से ज्यादा दिव्यांगों को आवश्यक सहायता उपकरण दिए गए हैं। ये कैंप गिनीज बुक तक में दर्ज हो रहे हैं।

सरकारी नौकरी में उनके लिए आरक्षण भी 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। दिव्यांगों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून में भी बदलाव किया गया है। देश भर में दिव्यांगों की एक ही common sign language विकसित की जा रही है। सवा सौ करोड़ लोगों का हमारा देश संसाधनों से भरा हुआ है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022, देश जब आज़ादी के 75वें वर्ष में पहुँचेगा तब क्या हम सब मिल कर महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, बाबासाहेब अंबेडकर और स्वराज्य के लिए अपना जीवन देने वाले अनगिनत वीरों के सपनों के भारत को साकार कर सकते है? हम में से प्रत्येक संकल्प ले - परिवार हो, संगठन हो, इकाइयों हो - आने वाले पाँच साल पूरा देश संकल्पित होकर नये भारत, न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में जुट जाए। सपना भी आपका, संकल्प भी, समय भी आपका, समर्पण भी आपका और सिद्धि भी आपकी।

न्यू इंडिया, सपनों से हकीक़त की ओर बढ़ता भारत।
न्यू इंडिया, जहां उपकार नहीं, अवसर होंगे
न्यू इंडिया की नींव का मंत्र, सभी को अवसर, सभी को प्रोत्साहन
न्यू इंडिया, नयी संभावनाओं, नये अवसरों का भारत।
न्यू इंडिया, लहराते खेत, मुस्कुराते किसानों का भारत।
न्यू इंडिया, आपके हमारे स्वाभिमान का भारत। ■

भारत अब अनाज का निर्यात करने वाला देश: केन्द्रीय कृषि मंत्री

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने नई दिल्ली में 18 मार्च को कमोडिटीज मार्केट पर आयोजित सम्मेलन को सम्बोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि सरकार किसानों को मार्केट से जोड़ने और उनके लिए एक ठोस मार्केटिंग ढांचा खड़ा करने का प्रयास कर रही है ताकि देश के किसान खेती के साथ फसलों से जुड़े व्यापार में हिस्सेदारी करें और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उत्पादन बढाने, उत्पादन लागत कम करने तथा आय के अन्य सहायक स्रोतों को अपनाने के साथ किसानों की उपज की सही मार्केटिंग का इंतजाम करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें जिंसों के डेरीवेटिव्स व्यापार, मूल्य खोज एवं मूल्य जोखिम प्रबंधन में सहायक हो सकता है और अर्थव्यवस्था के सभी वर्ग के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यह कृषि जिंसों की मांग और पूर्ति के असुंतलन को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने कहा कि वायदा कारोबार सिर्फ आज के बाजार के मूल्य संकेत नहीं देता, अपितु आने वाले कुछ महीनों के लिए भी मूल्य संकेत देता है जिससे क्रेता और विक्रेता दोनों ही आने वाले समय में अपनी खरीद बिक्री की योजना बना सकते हैं जिससे मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रह सके। इस तरह यह किसान और उपभोक्ता दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे किसान पहले ही योजना बना सकते हैं कि उन्हें कब, कौन सी और कितनी फसल की खेती करनी है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि बाजार किसानों की पहुच के अन्दर हो तथा बाजार व्यवस्था में बिचौलिये नहीं हों। उन्होंने कहा कि उपज का मूल्य पारदर्शी तरीके से तय होना चाहिए और किसान को अपनी उपज का अविलंब मूल्य मिलना चाहिए। साथ ही, किसान और बाजार के बीच की दूरी यथासंभव कम होनी चाहिए।

आजादी के बाद से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर और अन्य देशों के लिए अनाज का निर्यात करने वाला देश बन गया है। कृषि विकास दर 2% से बढ़कर 4.4% हो गई है जो यह दर्शाती है कि सरकार किसानों और कृषि की भलाई के लिए गंभीरता से काम कर रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि उपज का संगठित विपणन राज्य सरकारों द्वारा विनियमित मंडियों द्वारा किया जाता है, जिनकी कुल संख्या देश में 6746 है। किसानों पर गठित राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसा के अनुसार 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक मंडी होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में लगभग 580 वर्ग किलोमीटर में एक मंडी है। वर्तमान सरकार एपीएमसी मंडी खोलने के साथ विपणन कानूनों में सुधार करवाकर निजी क्षेत्र में भी मंडी स्थापित करवाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार खाद्य भंडारों को बजार सब यार्ड में विकसित करने पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि ई-नैम के द्वारा किसानों की पहुंच देश के अनेक मंडियों एवं क्रेताओं से स्थापित हो रही है। ई-नैम के जरिए किसान किसी भी जगह बैठकर ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा अपनी फसल को बेच सकता है तथा इसके लिए वह उपज की गुणवत्ता अनुरूप उत्तम मूल्य प्राप्त कर सकता है। यदि उसे मूल्य पसंद न हो तो वह ऑनलाइन द्वारा की गयी सर्वोच्च बोली को भी नकार सकता है। इसमें किसान को अपने फसल की धनराशि का ऑनलाइन भुगतान सीधे उनके खाते में प्राप्त होती है। ई-नाम पोर्टल से वर्ष 2018 तक कुल 585 मंडियों को जोड़े जाने की योजना है । अब तक 12 राज्यों के 277 मंडियों को ई-नैम से जोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर और अन्य देशों के लिए अनाज का निर्यात करने वाला देश बन गया है। कृषि विकास दर 2% से बढ़कर 4.4% हो गई है जो यह दर्शाती है कि सरकार किसानों और कृषि की भलाई के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल बजट की तुलना में वर्ष 2017-18 के बजट में, ग्रामीण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए निधि में 24% की वृद्धि हुई है, अब यह 1,87,223 करोड़ रुपये है। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टप्स के लिए निधि स्थापित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 मार्च को स्टार्टप्स के लिए निधि स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमति प्रदान कर दी है। इसे पिछले साल जून में 1,000 करोड़ रुपये के साथ इसे स्थापित किया गया था। गजट अधिसूचना जी एस आर 180 17-02-2016 के मुताबिक स्टार्टप्स निधि द्वारा सहायता प्राप्त वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को कम से कम दो बार निवेश किया जा सकेगा। अगर स्टार्ट-अप समाप्त होने से पहले पूरी तरह से स्टार्ट-अप के लिए प्रतिबद्ध राशि को जारी नहीं किया गया है तो शेष राशि उसके बाद जारी रह सकती है।

यह भी निर्णय लिया गया कि एआईएफ और बकाया के लिए किए गए प्रतिबद्धताओं के 0.50% की सीमा तक एफईएस से ली जाएगी जिससे वेंचर कैपिटल इनवेस्टमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन, कानूनी और तकनीकी मूल्यांकन के लिए परिचालन व्यय आदि की पूर्ति होगी। प्रत्येक आधे वर्ष की शुरुआत में (एक अप्रैल और एक अक्टूबर को) इसे फंड में निकासी की जाएगी।

केंद्रीय कैबिनेट की 22-06-2016 को हुई बैठक में स्टार्टअप्स के लिए निधि स्थापित करने का फैसला लिया था जिसके लिए 1000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी। यह योगदान 14वें और 15वें वित्त आयोग के धनराशि की चक्रीय उपलब्धता और कार्यान्वयन की प्रगति के लिहाज से किया गया था। बैठक में एफएफएस वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के लिए धन प्रदान करने का फैसला लिया गया। एफएफएस का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की देखरेख में होता है। सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में एफएफएस योगदान करता है। यह योगदान अधिकतम 35 प्रतिशत से अधिक तक हो सकता है।

उसी बैठक में कैबिनेट ने फैसला किया कि एआईएफ द्वारा जुटाया गया फंड पूरे स्टार्टप्स में निवेश किया जाएगा। विभिन्न हितधारकों के साथ अपनी बातचीत के दौरान यह विभाग को सूचित किया गया है कि एआईएफ में निवेशकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे एआईएफ का पोर्टफोलियो निवेश के जोखिम को उचित रूप से प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त रूप से विविध है और अगर एआईएफ के संपूर्ण धन को स्टार्ट-अप में निवेश किया जाता है तो यह ऐसे एआईएफ के निवेशकों के लिए अस्वीकार्य जोखिम बना हुआ है।

जिन अन्य मुद्दों को लेकर हितधारकों ने चिंता जाहिर की उनमें एआईएफ द्वारा स्टार्ट-अप के वित्तपोषण की प्रक्रिया लंबे समय से तैयार की गई है जो एआईएफ द्वारा शुरूआती प्रतिबद्धता से शुरू होती है और फिर फंड्स में फंड जारी करता है, शामिल है। इस प्रकार यह संभव है कि अंतिम किस्त के जारी किए जाने से पहले स्टार्ट-अप का कारोबार 25 करोड़ रुपये हो, लेकिन इसकी अभी भी अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्टार्ट अप को अपने जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के माध्यम से धन जुटाने की आवश्यकता होती है अर्थात प्रारंभिक चरण, बीज स्तर और विकास मंच पर। सिडबी द्वारा विभाग को भी बताया गया कि वर्तमान प्रावधान एआईएफ को स्वीकृति के बाद की गई गतिविधियों के लिए सिडबी को मुआवजा देने के लिए अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। ■

दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में सर्वप्रथम

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश अब खाद्यान्न में आत्म निर्भर है और दूसरे देशों को अनाज का निर्यात कर रहा है। दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में सर्वप्रथम है। दुग्ध उत्पादन वर्ष 2013-14 में 137.61 मिलियन टन से वर्ष 2014-15 में 146.31 मिलियन टन हो गया व 2015-16 में 155.49 मिलियन टन हुआ। नई योजना "राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन" की शुरुआत नवम्बर 2016 में रु. 825 करोड़ की लागत के साथ की गयी है। वर्ष 2015-16 के दौरान 82,930 मिलियन अंडों का उत्पादन हुआ। श्री सिंह ने यह बात 15 मार्च को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में तीन दिनों तक चलने वाले कृषि उन्नति मेला 2017 के उद्घाटन पर कही।

श्री सिंह ने कहा कि मात्स्यिकी में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए मोदी सरकार ने मात्स्यिकी क्षेत्र में 'नीली-क्रांति' का आह्वान किया है। नीली क्रांति' योजना के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए रु. 3000 करोड़ का केन्द्रीय बजट तय किया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या 665 तक पहुंचा दी गयी है जिससे किसान प्रशिक्षण लेकर नई कृषि तकनीकों को अपना सके। कैबिनेट ने 3960 करोड़ रुपये की स्वीकृति कृषि विज्ञान केन्द्रों को चलाने के लिए दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लैब टू लैंड, पानी, मिट्टी, उत्पादकता, खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष बल दिया है। इनमें फार्मर फर्स्ट, आर्या, स्टूडेन्ट रेडी, मेरा गांव-मेरा गौरव नाम प्रमुख हैं। ■

अटल मिशन (अमृत) के तहत उत्तर प्रदेश में 11,421 करोड़ रुपये का निवेश

अटल मिशन के अंतर्गत यह सबसे बड़ा निवेश

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत उत्तर प्रदेश में 11,421 करोड़ रुपये की कुल धनराशि खर्च की जाएगी। इसके अंतर्गत वर्ष 2019-20 तक 1 लाख से अधिक आबादी वाले 61 शहरों और नगरों में बुनियादी शहरी संरचना में सुधार किया जाएगा। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लिए अमृत कार्य योजना को स्वीकृति दी है जो 2017–2020 के दौरान चलेगी। इसकी कुल लागत 4,239 करोड़ रुपये वार्षिक कार्य योजना के तहत यानी 2015-16 और 2016-17 के संदर्भ में है। अटल मिशन के अंतर्गत यह सबसे बड़ा निवेश है।

तमिलनाडु के लिए वर्ष 2017–2020 के दौरान 4,154 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। इस तरह 33 शहरों में कुल मिशन निवेश 11,237 करोड़ रुपये का है। महाराष्ट्र में 44 मिशन शहरों और नगरों के लिए 2015-20 के दौरान बुनियादी शहरी संरचना में सुधार के लिए 6,759 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसी तरह हरियाणा में 20 मिशन शहरों और नगरों के लिए 2017-20 के दौरान बुनियादी शहरी संरचना में सुधार के लिए 2,544 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में 9 मिशन शहरों और नगरों के लिए 2015-20 के दौरान बुनियादी शहरी संरचना में सुधार के लिए 2,192 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसी तरह मणिपुर में एकमात्र शहर इम्फाल में बुनियादी शहरी संरचना में सुधार के लिए 180 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। सिक्किम में एकमात्र शहर गंगटोक के लिए 2015-20 के दौरान बुनियादी शहरी संरचना में सुधार के लिए 39 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। ■

अयोध्या में बनेगा रामायण संग्रहालय

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कहा है कि अयोध्या में रामायण संग्रहालय बनाने के लिए प्रदेश सरकार जमीन देगी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री महेश शर्मा से मुलाकात की। गौरतलब है कि श्री शर्मा ने पिछले वर्ष संग्रहालय के लिए प्रस्तावित स्थल का दौरा किया था। योगी आदित्यनाथ ने 21 मार्च को कहा कि 'रामायण संग्रहालय के लिए तैयारी शुरू कर दें, एक हफ्ते में जमीन मिल जाएगी।' केंद्र सरकार ने पहले ही संग्रहालय के लिए 151 करोड़ रुपए आबंटित कर दिए हैं। साथ ही नेपाल और श्रीलंका में मौजूद रामायण से जुड़े विभिन्न स्थानों को भी संग्रहालय के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। ■

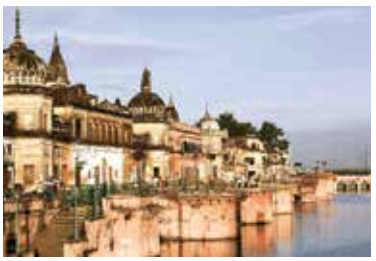

एनटीपीसी ने 263.95 अरब यूनिट बिजली का सर्वाधिक उत्पादन किया

मौजूदा वर्ष में एनटीपीसी समूह ने अब तक का सबसे अधिक 263.95 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन किया है जो पिछले वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन 263.42 अरब यूनिट से अधिक है। इस तरह इस वर्ष एनटीपीसी ने पिछले वर्ष की तुलना में 4.71 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की।

एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता 48,188 मेगा वॉट है, जिसमें 19 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 10 सौर ऊर्जा आधारित और 1 पन बिजली संयंत्र शामिल हैं। इनके अलावा 9 सहायक /संयुक्त उपक्रम वाले बिजली घर भी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी की पहली कोयला खान हजारीबाग में पकरी-बड़वाडीह दिसंबर, 2016 में चालू हो गई थी। कंपनी की पहली पवन ऊर्जा परियोजना गुजरात में शुरू हुई थी। एनटीपीसी ने अभी हाल में देश के सबसे बड़े 100 केडब्ल्यूपी फ्लोटिंग सोलर पीवी संयंत्र का उद्घाटन किया जिसे केरल में लगाया गया है। ■

प्रधानमंत्री निवास पर भाजपा सांसदों के साथ बैठकें

उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ प्रधानमन्त्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का वार्तालाप

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह पिछले तीन सालों से, संसद के हर एक सत्र के दौरान, भाजपा के सांसदों के गुट बनाकर अनौपचारिक बैठक का आयोजन करते हैं। इन बैठकों में अपने क्षेत्र और प्रदेश के विकास, भारत सरकार की जनहित की योजनाएं, संसद के कार्यकलाप और सामयिक विषयों के बारे में, सांसदों का दायित्व के सन्दर्भ में संवाद गोष्ठी करते हैं।

इस कड़ी में, वर्तमान संसद सत्र के दौरान, प्रधानमन्त्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश भर के भाजपा सांसदों से वार्तालाप करने के लिए प्रधानमंत्री निवास पर जलपान बैठकों का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की प्रथम बैठक संपन्न हुई जिसमें गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, भाजपा के वरिष्ठ सांसद श्री मुरली मनोहर जोशी और संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार उपस्थित थे।

उपस्थित सभी सांसदों ने श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह का अभिवादन गर्मजोशी से किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अथक परिश्रम करने के लिए सभी सांसदों को धन्यवाद दिया।

श्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में, भाजपा के सांसदों के दायित्व

की सक्रियता को गतिमान बनाने के लिए प्रेरणा दी और 15 साल के लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, जन सेवा और विकास के लिए पूरी शक्ति के साथ कार्यरत हो गयी है तब उसकी सफलता और सुशासन का निर्माण करने के लिए, उत्तर प्रदेश को बीमारू स्थिति से निकलकर सुचारु उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, जन अपेक्षा की पूर्ति और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रस्थापित करने के लिए तथा भाजपा की नयी सरकार को पूरा सहयोग देने का आग्रह किया। ■

गोवा, गुजरात और राजस्थान एवम् दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंडमान और निकोबार प्रदेशों के सांसदों के साथ विचार-विमर्श

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को प्रधानमंत्री निवास पर अनौपचारिक बैठक में पश्चिम भारत के गोवा, गुजरात और राजस्थान राज्यों एवम् दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंडमान और निकोबार के केंद्र शासित प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी के लोक सभा और राज्य सभा के सांसदों के साथ भाजपा के नेतृत्व में कार्यरत भारत सरकार और सम्बंधित राज्य सरकारों की जन-कल्याण योजनाएं और विकास कार्यक्रमों के सन्दर्भ में, भाजपा सांसदों के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श किया।

प्रधानमंत्री निवास पर भाजपा सांसदों के गुटों के साथ अनौपचारिक जलपान बैठकों के उपक्रम का यह दूसरा चरण था जिसमें राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, वरिष्ठ सांसद श्री लाल कृष्ण अडवाणी और संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार उपस्थित थे।

सांसदों ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का ब्यौरा दिया और सभी जन- समुदायों में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सहित चार राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक विजय और जन समर्थन की लहर चली इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह के यशस्वी नेतृत्व की गर्मजोशी से प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने सांसदों को जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अविरत परिश्रम करने का मार्गदर्शन दिया। भारत सरकार के विभिन्न जनकल्याण के कार्यों, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, महिला वर्ग और युवाओं सहित सामान्य जन जीवन में बदलाव ला रहें है और सांसदों का दायित्व इसे जन-जन तक पहुंचाना है - यह बात नरेंद्र मोदी जी ने विस्तार से कही। प्रधानमंत्री ने सांसदों को डिजिटल ट्रांजेक्शन एवम् सोशल मीडिया से जुड़ने का अनुरोध किया।

श्री अमित शाह ने बताया कि आगामी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूरे सप्ताह भर सांसदों का क्षेत्रीय जन संचार अभियान संपन्न होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी कहा कि भारत सरकार ने नया NSEBC - सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय आयोग बनाने का और इसे संवैधानिक दर्ज देने का जो निर्णय लिया है वह देश के सभी पिछड़े वर्गों के हित में लाभदायी होगा। इस निर्णय की भूमिका की समझ श्री अमित शाह ने दी और कहा की नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार द्वारा गठित यह नया आयोग पिछड़े वर्गों के जीवन में बदलाव लाने के लिए दूरगामी सिद्ध होगा। ■

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष के निमित्त आयोजित राष्ट्रीय बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, साथ में– भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय महामंत्री सर्वश्री अरुण सिंह एवं कैलाश विजयवर्गीय।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर भेंट करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने कमल संदेश के आजीवन सदस्य

कमल संदेश की कैशलेस सदस्यता लें!

आह्वान

आपको जानकर हर्ष होगा कि 6 दिसम्बर 2016 को पार्टी मुख्यालय में भाजपा 'कमल संदेश' का आजीवन सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. **श्री अमित शाह** ने पत्रिका की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 'कमल संदेश' भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय पत्रिका है और यह पाक्षिक रूप में हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है।

हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं 5000/– रुपए का चैक देकर 'कमल संदेश' की आजीवन सदस्यता ली। साथ ही केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर सहित अनेक केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आजीवन सदस्यता ग्रहण की गई है।

'कमल संदेश' हिन्दी एवं अंग्रेजी के दोनों अंकों को 5000/– (पांच हजार रुपये) की सदस्यता शुल्क देकर नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब 'कमल संदेश' के लिए कैशलेस भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है। कृपया 5000/– (पांच हजार) रुपये का योगदान कर आप भी 'कमल संदेश' (हिन्दी+अंग्रेजी) का आजीवन सदस्य बनें।

एक साल (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹350/-	**तीन साल** (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹1000/-
आजीवन (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹3000/-	**आजीवन** (हिन्दी+अंग्रेजी)	—	₹5000/-

'कमल संदेश' के हमारे पाठकों से अनुरोध है कि इसकी सदस्यता लेकर जीवंत वैचारिक आंदोलन के भागीदार बनें।

कैशलेस बना 'कमल संदेश' सदस्य बनें और बनाएं

☞ **www.kamalsandesh.org, www.bjp.org** पर जाकर कैशलेस भुगतान क्रेडिट/डेबिट/नेटबैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।

☞ साथ ही दिए बार कोड से मोबाइल द्वारा सीधा भुगतान भी कर सकते हैं।

chillr
ACCEPTED HERE
Scan the QR code to make a payment
Click on **SCAN & PAY** and enter amount
Add this contact to pay
+91 9911026172

"**कमल संदेश**" के नाम से कृपया चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
कमल संदेश, पीपी–66, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली– 110003